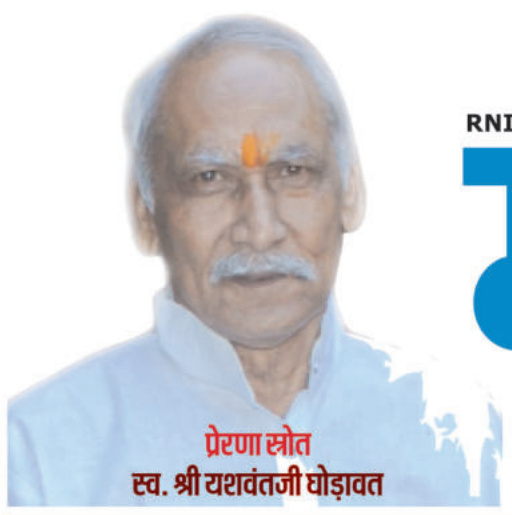

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली न चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वकांक्षा नहीं रख सकता।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

वर्ष-07, अंक - 39 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 19 जून 2025 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

भारत-कनाडा के बीच सहमति, सुधरेंगे संबंध

नई दिल्ली, एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानास्किस में आयोजित समूह-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से भेंट की। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर सहमति बनी। भारत और कनाडा ने राजनयिक संबंधों को फिर से सामान्य करने और नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की है। अब यह उम्मीद की जा रही है कि भारत-कनाडा के बीच संबंधों में सुधार होगा और दोनों देश सकारात्मक दिशा में कार्य करेंगे।

कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने नागरिकों के लिए राजनयिक सेवाएं सामान्य करने और पिछले वर्ष निष्कासन के बाद से रिक्त पड़े प्रमुख पदों पर नियुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही है।

बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने समूह-7 सम्मेलन की सफल मेज़बानी के लिए मार्क कार्नी और कनाडा को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सामाजिक मंच एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बेहतरीन बैठक हुई। समूह-7 शिखर सम्मेलन की सफल मेज़बानी के लिए उन्हें और कनाडा सरकार को बधाई देता हूँ।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा, भारत और कनाडा लोकतंत्र और विधि के शासन में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री कार्नी और मैं भारत-कनाडा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करने को तत्पर हैं।

उल्लेखनीय है कि बीते कुछ महीनों में भारत और कनाडा के संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। ऐसे में उच्चायुक्तों और राजनयिकों की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

गौरतलब है कि कनाडा सरकार ने बीते वर्ष भारतीय अधिकारियों पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था, हालांकि उसने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद कनाडा ने भारत के छह राजनयिकों और वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को निष्कासित कर दिया था। जवाब में भारत ने भी कनाडा के उच्चायुक्त सहित छह अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया था।

देश को मिला पहला शैलो वॉटर क्राफ्ट

विशाखापट्टनम, एजेंसी।

भारत को अपनी पहली पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता वाला शैलो वॉटर क्राफ्ट 'आईएनएस अर्णाला' मिल गया है। बुधवार को इसका औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में समावेश किया गया। यह समारोह विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान उपस्थित रहे।

आईएनएस अर्णाला का नाम महाराष्ट्र के वसई स्थित ऐतिहासिक अर्णाला किले के नाम पर रखा गया है। यह पोत हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की उपस्थिति को और मजबूत करेगा। इसकी विशेषता यह है कि यह कम गहराई वाले समुद्री क्षेत्र में शत्रु की पनडुब्बियों का पता लगाने, उनका पीछा करने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है।

यह युद्धपोत भारतीय नौसेना को 8 मई को सौंपा गया था, और आज की कमीशनिंग सेरेमनी उसके सक्रिय रूप से सेवा में शामिल होने का प्रतीक है। यह पोत कुल 16 पनडुब्बी रोधी शैलो वॉटर क्राफ्ट में से पहला है जिसे सेवा में सम्मिलित किया गया है।

'अर्णाला' को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत मेसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता तथा मेसर्स एलएंडटी शिपबिल्डर्स के सहयोग से तैयार किया गया है। यह रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह जहाज लगभग 80 प्रतिशत स्वदेशी है।

15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस सूरत (विध्वंसक पोत), आईएनएस नीलगिरि (गुप्त रूप से कार्य करने वाला फ्रिगेट) और आईएनएस वाघशीर (पनडुब्बी) को कमीशन किया था और कहा था कि ये आधुनिक युद्धपोत नौसेना की शक्ति को नई ऊँचाइयों तक ले जाएंगे।

आईएनएस अर्णाला का प्रतीक चिह्न ÷अर्णवे शौर्यम्÷ (समुद्र में साहस) इसकी वीरता और साहसी उपस्थिति को दर्शाता है। यह जहाज भारत की समुद्री सीमा सुरक्षा को और अधिक मज़बूती प्रदान करेगा तथा हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं केवल एक राज्यभाषा है- राज ठाकरे

मुंबई।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली से पाँचवीं कक्षा तक हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के निर्णय पर विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, यह केवल एक राज्य की भाषा है और इसे बच्चों पर थोपना उचित नहीं है।

राज ठाकरे ने बताया कि उन्होंने 17 जून को राज्य सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि हिंदी को अनिवार्य भाषा न बनाया जाए। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि सरकार यह निर्णय वापस ले रही है, इसी के आधार पर उन्होंने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्र भेजा है।

राज ठाकरे ने कहा, बच्चों को कौन-सी भाषा सीखनी है, यह उन्हें बड़े होकर स्वयं तय करने दीजिए। उन पर हिंदी थोपना उचित नहीं। क्या यहां भी प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की लॉबी का दबाव काम कर रहा है?

उन्होंने सवाल किया कि यदि हिंदी को महाराष्ट्र में तीसरी अनिवार्य भाषा बनाया जा रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश में मराठी भाषा पढ़ाई जाएगी? क्या गुजरात में हिंदी अनिवार्य है?

शिक्षा मंत्री का बयान है कि यह तीसरी भाषा वैकल्पिक है, तो फिर इसे पहली कक्षा से क्यों लागू किया जा रहा है? इसे छठी कक्षा से क्यों नहीं शुरू किया गया?

महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुसार अब राज्य के मराठी और अंग्रेज़ी माध्यम के सभी विद्यालयों में पहली से पाँचवीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया है। केवल वही विद्यार्थी इसके स्थान पर अन्य भाषा चुन सकते हैं, जिनकी संख्या एक कक्षा में 20 से अधिक हो।

इस निर्णय को लेकर जहां एक ओर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाषा और पहचान की राजनीति ने फिर से ज़ोर पकड़ लिया है।

ज्वालामुखी संकट के चलते एयर इंडिया की फ्लाइट लौटी

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडोनेशिया के बाली के लिए दिल्ली से रवाना हुई एयर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ान एआई 2145 को बीच रास्ते से ही वापसी करनी पड़ी। बाली के पास ज्वालामुखी में गतिविधि की चेतावनी के बाद सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया गया। फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित उतारे गए। एयर इंडिया ने इस पूरी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी जोखिम से बचने के लिए उड़ान को लौटाने का फैसला लिया गया। एयरलाइन ने यात्रियों की असुविधा के लिए खेद जताया है और उनके लिए दिल्ली में ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है। यात्रियों को या तो पूरा पैसा लौटाया जा रहा है या बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उन्हें अगली उड़ान में समायोजित किया जा रहा है। इसी दौरान, दिल्ली में मंगलवार शाम मौसम ने भी बाधा डाली। खराब मौसम के चलते 14 उड़ानों का मार्ग बदलकर अन्य शहरों की ओर भेजना पड़ा। इनमें भोपाल, चंडीगढ़, अमृतसर, अहमदाबाद, वाराणसी और लखनऊ शामिल हैं। उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइट राडार 24 के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर 400 से ज्यादा उड़ानें विलंबित हुईं और कई को रद्द करना पड़ा।

परमाणु हथियार बना रहा चीन, दुनिया के लिए बढ़ता खतरा

नई दिल्ली, एजेंसी।

स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (सिप्री) की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के भंडार को अत्यधिक तेज़ी से बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार चीन हर वर्ष लगभग 100 परमाणु हथियार तैयार कर रहा है, जो भारत की तुलना में तीन गुना अधिक है।

सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2024 की शुरुआत तक चीन के पास लगभग 500 परमाणु हथियार थे, जो अब बढ़कर 600 हो चुके हैं। अनुमान है कि वर्ष 2035 तक यह संख्या 1,500 तक पहुंच सकती है। इस तेजी से हो रहे विस्तार ने विश्व शांति के लिए गंभीर चिंता पैदा कर दी है।

भारत के पास वर्तमान में लगभग 180 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170। भारत, पाकिस्तान से थोड़ी अधिक क्षमता रखता है, लेकिन दोनों देशों के बीच हाल की सैन्य तनातनी ने परमाणु युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया था।

रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका अब भी परमाणु हथियारों के मामले में शीर्ष स्थान पर हैं। दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इन्हीं दोनों देशों के पास है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही नए प्रकार के परमाणु हथियार विकसित करने और प्रक्षेपास्त्रों (मिसाइलों) पर कई हथियार एक साथ लगाने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अब अपने शुरुआती परमाणु त्रिकोण कृ यानी विमान से छोड़े जाने वाले बम, ज़मीन से छोड़ी जाने वाली प्रक्षेपास्त्रें तथा समुद्र से प्रक्षेपित की जाने वाली क्रूज़ प्रक्षेपास्त्रें कृ को विस्तार दे रहा है। वह अगस्ता-90बी डीजल-विद्युत पनडुब्बियों पर 'बाबर-3' नामक क्रूज़ प्रक्षेपास्त्रों को तैनात कर रहा है।

वहीं भारत के पास पहले से ही एक सशक्त परमाणु त्रिकोण मौजूद है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट नामक परमाणु ऊर्जा से संचालित बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र पनडुब्बियां पहले से सेवा में हैं, और तीसरी पनडुब्बी 'आईएनएस अरिधमन' को इसी वर्ष नौसेना में शामिल किए जाने की योजना है।

एसएसबीएन पनडुब्बियां समुद्र की गहराई से परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को दागने में सक्षम होती हैं, जिससे भारत की परमाणु क्षमता और भी सशक्त हो जाती है।

यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर शांति और सामरिक संतुलन की दृष्टि से गंभीर संकेत देती है कि यदि चीन इसी गति से परमाणु भंडार बढ़ाता रहा तो निकट भविष्य में वैश्विक स्थायित्व पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है।

नहीं सुना पक्षः ना इस्तीफा दूंगा, ना सेवा निवृत्ति लूंगा - न्यायमूर्ति श्री वर्मा

नई दिल्ली, एजेंसी।

जली हुई करेंसी मिलने के मामले में घिरे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने पद छोड़ने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र में इस पूरे घटनाक्रम को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया।

न्यायमूर्ति वर्मा ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं दिया गया। 6 मई को लिखे पत्र में उन्होंने 4 मई को भेजे गए प्रधान न्यायाधीश के उस पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें पद त्यागने की सलाह दी गई थी।

वर्मा ने लिखा, इस सलाह को स्वीकार करना ऐसा होगा जैसे मैं एकतरफा और अन्यायपूर्ण निर्णय को मान्यता दे रहा हूं। मुझे जांच रिपोर्ट के बाद केवल 48 घंटे में फैसला लेने को कहा गया, जो पूरी तरह अनुचित था।

यह विवाद उस समय उठा जब दिल्ली स्थित उनके आवास के एक हिस्से से जली हुई मुद्रा बरामद हुई। इसके बाद तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई गई, जिसने उन्हें दुराचार का दोषी बताया।

लेकिन वर्मा का कहना है कि न तो उन्हें पूरी जानकारी दी गई और न ही बचाव में कुछ कहने का अवसर मिला। उन्होंने न्यायिक मर्यादाओं की अनदेखी बताते हुए पूरे मामले की दोबारा समीक्षा की मांग की है।

अब यह मामला न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है।

बंगाली भाषियों को बनाया जा रहा निशाना- ममता बनर्जी

कोलकाता, एजेंसी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषा बोलने वाले नागरिकों को योजनाबद्ध तरीके से परेशान किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि जिनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं, उन्हें भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बताकर कार्रवाई की जा रही है।

विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान उन्होंने कहा, भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि वे देश के नागरिकों को केवल उनकी भाषा के आधार पर बांग्लादेशी कह रहे हैं। हमें गुजराती, मराठी, हिंदी और बंगाली जैसी सभी भाषाओं पर गर्व होना चाहिए। मैं स्वयं इन सभी भाषाओं में संवाद कर सकती हूं।

मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य के बाद भाजपा विधायकों ने सदन में जोरदार विरोध किया।

ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जिन लोगों को बांग्लादेश भेज दिया गया था, वे अब वापस आ चुके हैं। यह केवल राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि गंभीर मामला है, हालांकि उनकी बातों को कुछ हल्के तर्क भी कहा जा रहा है क्योंकि जिन लोगों को वापस लाया गया, उनके मामलों में कागजातों की स्थिति अस्पष्ट रही।

उदाहरण के तौर पर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के रहने वाले महबूब शेख को महाराष्ट्र पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी होने के संदेह में पकड़कर सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया था। सीमा सुरक्षा बल ने उन्हें बांग्लादेश भेज दिया, लेकिन ममता सरकार के हस्तक्षेप के बाद उन्हें पुनः भारत वापस लाया गया।

इसी तरह उत्तर 24 परगना जिले के बगदाह क्षेत्र के हरिहरपुर गांव से काम की तलाश में महाराष्ट्र गए फाजेर मंडल और उनकी नवविवाहिता पत्नी तस्लीमा के साथ भी यही घटना घटी। विवाह के कुछ ही दिन बाद वे निर्माण कार्य में रोजगार के लिए महाराष्ट्र पहुंचे थे, लेकिन वहां की पुलिस ने उन्हें संदेह के आधार पर बांग्लादेश भेज दिया।

फाजेर मंडल ने अपनी पहचान के लिए आधार और मतदाता पहचान पत्र दिखाए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि वे आधार या पैन कार्ड को नागरिकता के ठोस प्रमाण के रूप में नहीं मानते, क्योंकि इनका दुरुपयोग हो सकता है।

पुलिस की ओर से कहा गया कि महबूब शेख जन्म प्रमाण पत्र या पारिवारिक पहचान से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके, इसीलिए कार्रवाई की गई।

हालांकि सवाल यह उठ रहा है कि यदि वे वास्तव में विदेशी होते तो क्या उन्हें दोबारा भारत लाया जा सकता था? इससे यह संकेत मिलता है कि संबंधित व्यक्तियों के पास आवश्यक दस्तावेज हो सकते हैं।

ममता बनर्जी ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और यह स्पष्ट किया जाए कि कहीं पुलिस ने जानबूझकर पेश किए गए वैध दस्तावेजों की अनदेखी तो नहीं की।

संगठन सृजन बैठक में हुई मारपीट, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई - प्रदेश अध्यक्ष

माही की गूंज, भोपाल।

प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी और अनुशासनहीनता एक बार फिर सामने आई है। राजधानी भोपाल में आयोजित संगठन सृजन अभियान की बैठक के दौरान दो गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद और हाथापाई हुई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल माध्यमों पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

मंगलवार को मध्य विधानसभा क्षेत्र की बैठक भोपाल के एक भोजनालय में आयोजित की गई थी। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की पर्यवेक्षक यशोमती ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर विवाद

शुरू हो गया, जो आगे चलकर हाथापाई में बदल गया।

विवाद में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और कांग्रेस नेता साजिद अली के समर्थकों के बीच गाली-गलौज और मारपीट हुई।

यह कोई पहली घटना नहीं है जब कांग्रेस के कार्यक्रम में इस तरह की अनुशासनहीनता देखी गई हो, इससे पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं।

वहीं, प्रदेश शासन के एक मंत्री और भाजपा नेता विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी में ÷गुंडों का निर्माण÷ हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुटों में बंटी हुई है, और अब उसकी बैठकों में लात-घूंसे चलना आम बात हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान महिला नेताओं को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। सारंग ने यह भी कहा कि कांग्रेस में अब कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं बची है, सभी नेता सिर्फ अपने गुटों के लोगों को ज़िला अध्यक्ष बनवाने की कोशिश में लगे हैं।

झांसी की रानी पर कांग्रेस विधायक का विवादित बयान

भोपाल।

मध्यप्रदेश कांग्रेस के कई नेता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को लेकर विवादित टिप्पणी की है। यह वीडियो 3 अक्टूबर 2015 को कांशीराम की पुण्यतिथि का बताया जा रहा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पराशर ने समाज माध्यम ÷एक्स÷ पर साझा किया है।

वीडियो में फूल सिंह बरैया यह कहते नजर आ रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में वीरगति नहीं पाई बल्कि ग्वालियर में आत्महत्या की थी। उन्होंने कहा दृ खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है... बुंदेलों के हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी है, सुनी ही है यह तो लिखी भी नहीं है, क्यों सुनते हो तुम? युद्ध का मैदान झांसी में था, लेकिन लक्ष्मीबाई मरी ग्वालियर में आत्महत्या करके। आत्महत्या करने वाले को वीरांगना कहते हो? अगर ऐसा है तो रोज जो 10 लड़कियां आत्महत्या करती हैं, उन्हें भी वीरांगना कहो। सोचो दिमाग से, मत मानो हर लिखी और सुनी बात को सच।

इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोकेंद्र पराशर ने कहा कि 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर इस तरह की ÷काली जुबान÷ का प्रयोग अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने तीखे शब्दों में बरैया के बयान की आलोचना की है।

फूल सिंह बरैया वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, और उनका यह बयान कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है।

डॉ.चोपड़ा होंगे मुख्य खंण्ड चिकित्सा अधिकारी

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक बार सीबीएमओ के पद पर डॉ.एम.एल.चौपड़ा एक बार फिर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देते नजर आयेंगे। इसके साथ ही कोरोना जैसी भयंकर बीमारी के चलते झकनावदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉ.चोपड़ा ने सेवाएं प्रदान करते हुए नगर व आसपास मे करीबन 40 गांवों के मरीजों को अपनी सेवाएं दी थी। डॉ.एम.एल.चोपड़ा मेडिकल ऑफिसर के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झकनावदा पर वर्ष 2012 में पदस्थ हुए थे। वर्ष 2012 से लगाकर वर्ष 2023 तक झकनावदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए साथ ही वर्ष 2018 से सितंबर 2019 तक प्रभारी बीएमओ के पद पर रामा ब्लॉक में पदस्थ रहकर अपनी सेवाए दी और उसके पश्चात सितंबर 2019 से लगाकर 10 फरवरी 2023 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटलावद के प्रभारी बीएमओ के पद पर पदस्थ रहे।

प्रभारी सचिव पर कार्रवाई

माही की गूंज, झाबुआ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्र सिंह चौहान द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेटलावद द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार इस न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में सरपंच,सचिव की पेशी आयोजित की गई। निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए नियत की गई तिथि के उपरांत भी सरपंच,सचिव ग्राम पंचायत बैंगनबर्डी जनपद पेटलावद द्वारा 03 निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 10,01,103 का आहरण कर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने से इनके विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही के लिये आदेशित किया।

प्रकरण में ग्राम पंचायत बैंगनबडी के प्रभारी सचिव ऊँकार गामड द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप 15 दिवस का वेतन कटौत्रा करने हेतु आदेशित किया।

निम्न गुणवत्ता का निर्माण कार्य पर नोटिस

माही की गूंज, झाबुआ।

जनपद थांदला के ग्राम पंचायत कोटड़ा में आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केन्द्र और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत रुफ वॉटर हार्वेस्टिंग एवं हेण्डपम्प रिचार्ज पिट का निरीक्षण कलेक्टर ने किया।

दोनों ही निर्माणाधीन संरचना का निम्न गुणवत्ता का निर्माण कार्य होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सम्बन्धित सहायक यंत्री, उप यंत्री और ग्राम पंचायत के सचिव को नोटिस दिये जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। साथ ही आंगनवाड़ी केन्द्र के निर्माण कार्य का वैल्युएशन कराये जाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को दल के साथ आकर कार्य की गुणवत्ता की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया।

न्यायपालिका संविधान की रक्षा में कहां कर रहा है चूक....?

विविधताओं से भरे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। यह न केवल कानून की व्याख्या करती है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। लेकिन क्या ऐसा करते समय न्यायपालिका से कहीं न कहीं चूक हो जाती है...? या फिर जानबूझ कर अथवा अंजाने में कुछ न्यायविद किसी मुकदमे में फैसला सुनाते समय व्यक्तिगत हो जाते हैं, जिसको लेकर विरोधाभास भी हो जाता है। जबकि राष्ट्रहित और आतंकवादी घटनाओं से जुड़े मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप कई बार विवादों को जन्म देता है। नया कृषि कानून, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून में सुप्रीम कोर्ट की अति सक्रियता इसकी बड़ी मिसाल हैं। यह हस्तक्षेप कब रक्षक की भूमिका निभाता है और कब खतरनाक साबित हो सकता है, इसको लेकर अक्सर विवाद बना रहता है। आतंकवादियों को सजा सुनाने में देरी का मामला हो या फिर देश विरोधी ताकतों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खुली छूट को कानूनी संरक्षण देना इसी श्रेणी में आता है। संसद द्वारा बनाये गये कानून को बेवजह लटका देना भी न्यायपालिका के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना रहता है।

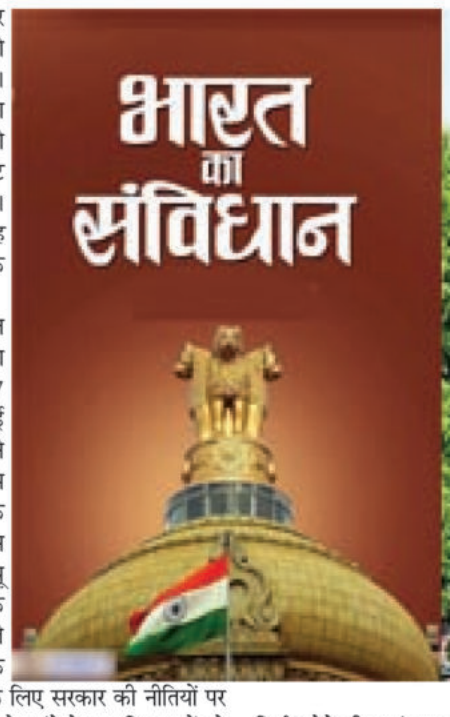

यहां सेना के एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे के बयान का जिक्र करना जरूरी है,जो 22 अप्रैल को पहलगाम में 27 हिन्दुओं की आतंकवादियों द्वारा की गई सामूहिक हत्या के बाद सामने आया था। पांडे ने तब कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि, सुप्रीम कोर्ट के जजों को पहलगाम जाना चाहिए, ताकि वे आतंकी हमले की वास्तविकता को समझ सकें। पांडे ने एक न्यूज एजेंसी को दिये इंटरव्यू में कहा था कि, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसके चलते सरकार और सेना के फैसलों में देरी हुई। उनके मुताबिक, जजों ने आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जो इस हमले का एक कारण बने। पांडे ने कहा कि, जजों को पहलगाम जाकर स्थानीय हालात, आतंकवाद का असर और सुरक्षाबलों की चुनौतियों को अपनी आंखों से देखना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि, कोर्ट को केवल कानूनी नजरिए से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत को समझकर फैसले लेने चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि, वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार और सेना को स्वतंत्र रूप से काम करने दे।

राष्ट्रहित एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें देश की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समरसता और संप्रभुता शामिल हैं। आतंकवाद, जो वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर चुनौती है, राष्ट्रहित को सीधे प्रभावित करता है। आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए सरकारें कठोर कानून बनाती हैं, जैसे यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम) या एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम)। इन कानूनों का उद्देश्य त्वरित कार्रवाई और अपराधियों को दंडित करना होता है, लेकिन कई बार ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का माध्यम भी बन जाते हैं। यहीं से न्यायपालिका की भूमिका शुरू होती है, जो सरकार की कार्रवाइयों की संवैधानिकता की जांच करती है।

आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर न्यायपालिका का अति-हस्तक्षेप कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। आतंकवादी गतिविधियां तेजी से बदलती है, और इनसे निपटने के लिए जांच एजेंसियों को त्वरित निर्णय लेने की स्वतंत्रता चाहिए। कई बार न्यायालयों के बार-बार के हस्तक्षेप से जांच प्रक्रिया बाधित होती है। उदाहरण के लिए, कुछ हाई-प्रोफाइल आतंकवादी मामलों में संदिग्धों को जमानत देना या सबूतों की स्वीकार्यता पर लंबी सुनवाई करना जांच को कमजोर कर सकता है। 2008 के मुंबई हमलों के बाद अजमल कसाब के मामले में न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करने में वर्षों लग गए, जिससे कई सवाल उठे कि क्या ऐसी प्रक्रियाएं आतंकवाद से लड़ने में बाधा बनती हैं!

न्यायपालिका के हस्तक्षेप का एक और खतरनाक पहलू तब सामने आता है, जब यह कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करती है। राष्ट्रहित से जुड़े मामलों, जैसे सीमा सुरक्षा या आतंकवाद-रोधी नीतियों में, कार्यपालिका को त्वरित और गोपनीय निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। यदि न्यायालय इन निर्णयों की बार-बार समीक्षा करने लगे, तो यह सरकार की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में यूएपीए के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को जमानत देने के निर्णय ने जांच एजेंसियों के मनोबल को कम किया। इससे यह धारणा बनी कि न्यायपालिका आतंकवाद के प्रति नरम रुख अपना रही है, जो जनता के बीच अविश्वास पैदा कर सकता है।

दूसरी ओर, न्यायपालिका का यह तर्क है कि वह केवल संविधान की रक्षा कर रही है। आतंकवाद से लड़ने के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। कई बार जांच एजेंसियां जल्दबाजी में या राजनीतिक दबाव में बिना पर्याप्त सबूत के लोगों को हिरासत में ले लेती हैं। ऐसे में न्यायालय का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए, हाल के कुछ मामलों में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन न्यायालय ने पाया कि उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे। इन मामलों में न्यायपालिका ने न केवल व्यक्तियों की स्वतंत्रता बहाल की, बल्कि सरकार को यह संदेश भी दिया कि कानून का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस द्वंद्व का एक और आयाम है जनता का विश्वास। आतंकवादी घटनाओं के बाद जनता त्वरित न्याय की अपेक्षा करती है। यदि न्यायपालिका बार-बार संदिग्धों को जमानत देती है या जांच प्रक्रिया में देरी होती है, तो यह जनता के बीच यह धारणा बना सकता है कि न्याय व्यवस्था कमजोर है। दूसरी ओर, यदि न्यायपालिका बिना पूरी जांच के कठोर सजा दे, तो यह निर्दोष लोगों के साथ अन्याय कर सकता है, जिससे समाज में असंतोष बढ़ेगा। दोनों ही स्थितियां लोकतंत्र के लिए हानिकारक हैं।

संजय सक्सेना

बहरहाल, इस समस्या का समाधान तभी संभव है, जब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच बेहतर समन्वय हो। आतंकवाद से निपटने के लिए कानून बनाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि वे संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन न करें। जांच एजेंसियों को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा, ताकि उनके कार्यवाही पर सवाल न उठें। साथ ही, न्यायपालिका को यह समझना होगा कि राष्ट्रहित और आतंकवाद जैसे मामलों में उसका हस्तक्षेप संतुलित होना चाहिए। अति-हस्तक्षेप से न केवल जांच प्रक्रिया बाधित होती है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बन सकता है।

वैसे सिक्के का दूसरा पहलू भी है। न्यायपालिका का हस्तक्षेप कई मामलों में राष्ट्रहित की रक्षा करता है। जब सरकार या जांच एजेंसियां बिना ठोस सबूत के किसी व्यक्ति को आतंकवादी गतिविधियों के लिए हिरासत में लेती हैं, तो न्यायालय उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। 1990 के दशक में टाडा (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम) के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए, जहां निर्दोष लोग लंबे समय तक जेल में रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर न केवल निर्दोषों को रिहा किया, बल्कि सरकार को कड़े कानूनों के दुरुपयोग पर चेतावनी भी दी। यह हस्तक्षेप लोकतंत्र की रक्षा करता है, क्योंकि बिना सबूत के हिरासत नागरिकों के विश्वास को कमजोर करती है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रहित और आतंकवादी घटनाओं से जुड़े मामलों में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने हस्तक्षेप में कितना संतुलन बनाए रखती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि न्यायपालिका को राष्ट्रहित के किसी मामले में संतुलन, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा, ताकि लोकतंत्र और देश की सुरक्षा दोनों बनी रहें।

ये कैसा भाजपा का सुशासन

माही की गूंज, खवासा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार सुशासन की परिभाषा बताते हुए कहा था कि, सुशासन में शासन स्वयं पात्र हितग्राही को उचित सहायता पहुंचाए न की हितग्राही, शासन व प्रशासन के ऑफिसो के चक्कर लगाए। इसी प्रकार भाजपा शासन में जीरो टॉलरेस का दावा किया जाता है। यानी किसी भी योजना में भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता होगी या अपराध करने वाले या नियम तोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव कठोरतम दंड देने की नीति के अनुसार चलना। लेकिन उक्त दोनो ही नीतिया खवासा की पेयजल योजना में नाकाफी साबित हुई है। जहां तक पात्र व्यक्ति को घर तक मदद पहुंचाने की नीति की बात है तो खवासा में पिछले कई वर्षों से पेयजल संकट बना हुआ है और गर्मी की ऋतु में यह और अधिक गहरा जाता है। जिसके लिए खवासावासियों के लिए जनभागीदारी अंतर्गत 50 लाख की नल जल योजना स्वीकृत की गई थी। लेकिन जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा सरकार में ही यह योजना मुर्तरूप नहीं ले पाई और 50 लाख की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई तथा खवासावासियो को पेयजल के लिए एक बूंद भी नहीं मिली। जबकि शासन व जनभागीदारी अंतर्गत 50 लाख रुपये खर्च किए गए। इस योजना में खवासा से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर स्थित ढोलखरा तालाब से पाइपलाइन के जरिए खवासा पानी लाया जाना था। लेकिन विडंबना देखिए सरकारी पाइपलाइन के साथ ही निजी पाइपलाइन भी डाली गई थी। लेकिन सरकारी पाइपलाइन में पानी नहीं आ पाया जबकि निजी पाईप लाइन द्वारा खवासा व सागवा तक के खेत में सिंचाई की जा रही है। ये है भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति!

दूसरी नीति है कि, पात्र हितग्राहियों को शासन खुद आगे आकर योजना का लाभ दिलाए। ऐसे में शासन की ये जिम्मेदारी है वो क्षेत्रवासियों को जल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रधानमंत्री स्वयं लाल किले की प्राचीर से हर घर पाइपलाइन के जरिए पानी देने की योजना का ऐलान करते हैं लेकिन वह योजना भी अधिकतर ग्रामों में शुरुआत के पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही है। खवासा को उस योजना में शामिल नहीं किया गया क्योंकि यहां पहले से ही नल जल योजना संचालित है। लेकिन कैसे संचालित है ये क` व ल खवासावासी ही समझ सकते हैं! बारहमासी जल संकट के चलते इस वर्ष ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में ही गांव की महिलाओं ने खाली बर्तनों के साथ एक प्रभावी रैली निकाली थी। ग्रहणियों द्वारा खवासा के इतिहास में किए गए पहले आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शासन प्रशासन के नुमाइंदे को कुंभकर्णी नींद से

फाईल फोटो : पेयजल समाधान के लिए धरने पर बेठी महिलाएं।

जगाने का था। लेकिन इस आंदोलन की गूंज सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच पाई और मोहन सरकार में नौकरशाही कितनी हावी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खाली बर्तनों की रैली के बाद प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था और उस ज्ञापन को सरकारी नुमाईंदे ने आगे पहुंचाना तक उचित नहीं समझा। मजबूरन महिलाओं को एक बार फिर आगे आना पड़ा। लगभग दो माह पश्चात महिलाओं ने आंदोलन की धार तेज करते हुए धरना प्रदर्शन का ऐलान किया और सुबह से प्रारंभ हुए धरने में दोपहर तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। जबकि धरने की सूचना पूर्व में ही दी जा चुकी थी। धरने के बाद प्रशासन को चक्काजाम की चेतावनी दी गई। जब जाकर प्रशासन हरकत में आया और अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। जहां अधिकारियों ने महिलाओं से चर्चा कर नर्मदा माइक्रो उद्वहन परियोजना क्रमांक 16 का आउटलेट खवासा क्षेत्र के तालाब क्रमांक 1 में पेयजल हेतु दिलाने का आश्वासन दिया गया। जिससे खवासावासियो को उम्मीद थी कि, खवासा को पेयजल संकट से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जल्दी ही यह आशा निराशा में बदल गई। जब नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 का पत्र क्रमांक/536/कार्य सीडब्ल्यु-05/2025 दिनांक 20 मई 25 को जारी हुआ। जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि, उक्त योजना केवल सिंचाई के लिए है जिसमें पेयजल का कोई प्रावधान नहीं है। यही नहीं योजना पूर्णता की ओर है ऐसे में इससे छेड़छाड़ किया जाना संभव नहीं है। ऐसे में हर खवासावासी के मन में एक ही प्रश्न है कि, यही बीजेपी का सुशासन है जिसमें महिलाओं के इतने उग्र प्रदर्शन के बावजूद शासन-प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा इस समस्या के स्थाई हल को खोजने में विफल रहा है। वह भी जब पिछले कई वर्षों से केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है। क्या सिंचाई योजना में से गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे खवासावासियो को नर्मदा जल की पाइपलाइन से एक आउटलेट नहीं दिया जा सकता है...?

इससे तो यही लगता है कि, शासन-प्रशासन किसी समस्या का हल चाहता ही नहीं है और शासन स्तर से ऐसी योजनाओं को ही स्वीकृति दी जाती है जिसमें भ्रष्टाचार किया जा सके आदि कई सवाल चौराहे की चर्चा में शामिल है।

बहरहाल खवासावासी एक बार फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। डबल इंजन में डबल विकास का दावा करने वाली भाजपा सरकार में ही खवासवासी गंभीर पेयजल संकट का सामना करने पर मजबूर है। शासन और प्रशासन को चाहिए कि अगर नर्मदा पाइपलाइन में आउटलेट देना संभव नहीं है तो तत्काल कोई दूसरी योजना बनाई जाए। ताकि वर्षों पुरानी इस समस्या का स्थाई हल किया जा सके। अन्यथा खवासा की महिलाएं एक बड़े आंदोलन की रूप रेखा बनाने से भी पीछे नहीं हटेगी। हर खवासावासी के मन में एक ही प्रश्न है क्या यही भाजपा का सुशासन व जीरो टॉलरेंस है...?

अनियंत्रित वाहन मकान में घुसा, बड़ी घटना टली

माही की गूंज, खवासा।

क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परवाड़ा मुख्य रोड पर मंगलवार 3 से 4 बजे के मध्य एक वाहन अधिक स्पीड होने के कारण स्कॉर्पियो जिसका वाहन क्रमाक एमपी 43 बीडी 1272 अनियंत्रित होते हुए एक मकान में जा घुसा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन इतनी अत्यधिक स्पीड में था कि, अगर कोई उसकी चपेट में आ जाता तो घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो जाती। हालांकि मौके पर कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है और ना ही कोई जनहानि हुई है। लेकिन गाड़ी सीधे ग्रामीण के मकान में घुस गई है जिसे देखने वालों की भीड़ लग गई।

ग्रामीणों के अनुसार जो युवक गाड़ी में थे वे अत्यधिक मात्रा में शराब पिए हुए थे। जिसकी वजह से गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठे और ग्रामीण के मकान में घुस गए। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, युवक जाबू खादन (बाजना) तरफ के बताए जा रहे हैं। भेरूपाड़ा में किसी जगह आए थे, उसके बाद खवासा तरफ जा रहे थे कि, गाड़ी नियंत्रित नही हई और सीधे ग्रामीणों के मकान में घुस गई।

श्री पाटीदार, जल संवर्धन योजना के सदस्य मनोनीत

माही की गूंज ,पेटलावद।

झाबुआ जिले के रायपुरिया निवासी मोहनलाल पाटीदार को दिल्ली में आयोजित आयोजन में वन पर्यावरण एवं जल संवर्धन का सदस्य मनोनीत किया गया। इनकी नियुक्ति वन पर्यावरण जल संवर्धन योजना के सेक्रेटरी अश्विनसिंह दिल्ली एवं वन पर्यावरण जल संवर्धन योजना के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारद्वाज के हाथों से नियुक्ति प्रदान दी गई। ग्राम रायपुरिया के कई मित्रों ने बधाई प्रेषित कर आगे बढ़ाने के लिए और कामना की। भारत सरकार द्वारा सदस्य मनोनीत मोहनलाल पाटीदार सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरण, वृक्षारोपण ऐसे अनेक कार्यों में अग्रणी रहते हुए इस मुकाम पर पहुंचे।

पानी की बौछार और किसान लगे बोवनी करने...

माही की गूंज, खवासा।

खवासा सहित आसपास ग्रामीण अंचलों में किसान इन दिनों खरीफ फ़सल को लेकर बोवनी की शुरुआत कर दी गई है। पानी की बौछार गिरने के बाद किसानों के चेहरों की खुशी के साथ खेत खलियान में लोग अपने कार्य में जुड़ गए हैं। तो वही सोयाबीन के साथ कपास व मक्का, मिर्ची, टमाटर की बोवनी की जा रही है।

किसान केशव सोलंकी, कमल चावड़ा, भारत खेर आदि ने बताया कि, अभी जैसे ही पानी गिरा तो खेतों में बोवनी शुरू कर दी गई है। मिर्ची और टमाटर को बाड़े में लगा रखा है, इनका पौधा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद और अधिक वर्षा होने के बाद उसको भी खेतों में लगाया जाएगा। अभी सोयाबीन, मक्का आदि की बोवनी का कार्य चल रहा है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मुक्केबाजी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर अनुशासनहीनता की तस्वीर सामने आई है। मंगलवार शाम को भोपाल के एमपी नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में चल रही 'संगठन सृजन अभियान' की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। जहां अंदर एआईसीसी पर्यवेक्षकों और स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में मध्य विधानसभा क्षेत्र की बैठक चल रही थी, वहीं बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और गाली-गलौज का दौर चला।

सूत्रों के अनुसार, यह हंगामा कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और कांग्रेस नेता साजिद अली के समर्थकों के बीच हुआ। दोनों पक्षों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। मारपीट और गाली-गलौज की इस घटना ने कांग्रेस की संगठनात्मक एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बैठक में एआईसीसी पर्यवेक्षक यशोमति ठाकुर सहित कई वरिष्ठ और स्थानीय नेता मौजूद थे, जो भोपाल जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा में व्यस्त थे। इस दौरान बाहर हुए इस हंगामे ने पार्टी के लिए शर्मिंदगी की स्थिति पैदा कर दी।

घटना के बाद दोनों पक्षों के कार्यकर्ता एमपी नगर थाने पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ शिकायती आवेदन दिए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस घटना पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक्स पर लिखा, ÷कांग्रेस की बैठक या कुश्ती प्रतियोगिता? भोपाल में कांग्रेस का संगठन सृजन अब संघर्ष सृजन बन गया है। जिला कांग्रेस की बैठक में आरिफ मसूद और साजिद अली के समर्थकों के बीच बहस नहीं, सीधे मारपीट हुई। आरोप लगा कि साजिद अली ने चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया- जवाब मिला, ÷बैठक में देशभक्तों की जरूरत नहीं।÷ फिर क्या था कृ बहस, धक्का-मुक्की और कुर्सियां चलने लगीं! अब समझ आया कि कांग्रेस में मन की बात नहीं, मुक्कों की बात होती है। अगली बैठक में डॉक्टर आएंगे या पुलिस? इंतज़ार कीजिए....÷

'संगठन सृजन अभियान' का शुभारंभ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीते 3 जून को भोपाल दौरे के दौरान किया था। इस अभियान के तहत कांग्रेस ने 61 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं पार्टी की आंतरिक कलह को उजागर कर रही हैं।

बदनावर-थांदला-टिमरवानी फोर लेन का सर्वे प्रारम्भ

सारंगी चौपाटी पर बनेगा ओवर ब्रिज, थांदला,पेटलावद, करडावद रहेंगे बायपास के दायरे में

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

आमतौर पर अधिकांश सरकारी काम कभी समय पर पूरे नहीं होते हैं। कई काम तो दो से तीन गुना समय बीतने के बाद भी अधूरे रह जाते हैं और उनकी गुणवत्ता भी स्तरहीन रहती है। लेकिन इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय अपवाद साबित हो रहा है। ऐसा ही एक कार्य बदनावर से पेटलावद, थांदला, टिमारवानी तक बनने वाला 86 किमी मार्ग फोर लेन मार्ग बनाया जा रहा है। जिसका सर्वे का कार्य प्रारम्भ हो गया है। इस मार्ग को बनाने के लिए 1900 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए है।

वैसे तो इसके पूर्ण होने की समय सीमा 2028 है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का दावा है इसे सिंहस्थ के पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। मार्ग का निर्माण भी आधुनिक और उन्नत तकनीक से किया जाएगा। क्योंकि यह मार्ग गुजरात एव राजस्थान राज्य को महाकाल लोक उज्जैन को जोड़ने का एक अति महत्वपूर्ण कड़ी है।

गौरतलब हैं कि, 9 अप्रैल को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस फोर लेन की घोषणा की थी। 2028 में होने वाले उज्जैन सिंहस्थ के पहले काम पूरा करने की योजना है। ऐसे में एनएचएआई काम में काफी तेजी दिखा रही है। एनएचएआई के अनुसार सर्वे पूरा होते ही जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। अभी रोड के आसपास के हिस्सों के साथ-साथ बायपास, ओवर ब्रिज, मेजर पुल व अंडरपास, पेटलावद, बामनिया रोड एव सारंगी चौपाटी पर ओवर ब्रिज, दिल्ली मुम्बई रेल मार्ग होने से यातायात अवरुद्ध न हो, इसलिए रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे।

भविष्य के यातायात के भारी दबाव को देखते हुए प्रत्येक लेन की चौड़ाई 9 मीटर रखी गई है। वलगभग 90 किलोमीटर के फोर लेन रोड की लागत 1900 करोड़ रुपये आंकी गई है।

बता दे कि, यह मार्ग 2022-23 में एमपीआरडीसी ने 432 करोड़ रुपये में टिमरवानी से बदनावर तक के अभी के 7 मीटर चौड़े रोड की जगह 10 मीटर का रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन इस बीच फोर लेन की घोषणा हो गई। अब इस पर फोर लेन बनाने पर काम किया जा रहा है।

सर्वे का कार्य शीघ्र होगा पूरा

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस 8 वे को महाकाल लोक उज्जैन से जोड़ने वाले टिमरवानी, थांदला पेटलावद होकर बदनावर को जोड़ने वाले फोरलेन का काम जल्दी शुरू होने की संभावना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसका सर्वे शुरू करा दिया है। 15 दिनों में सर्वे पूरा होने की संभावना है। खास बात ये है कि, इस फोरलेन के रास्ते में आने वाले दो शहरों और एक बड़े गांव में बायपास बनाए जाएंगे। वही सारंगी चौपाटी व पेटलावद-बामनिया रोड पर ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। फोर लेन के पहले सर्वे में थांदला, पेटलावद और करड़ावद में बायपास बनाने की तैयारी है।

नेशनल हाइवे बन जायेगा

उज्जैन से बदनावर तक 69.1 किमी यह मार्ग पहले स्टेट हाईवे-18 मार्ग था। वाहनों की बढ़ती संख्या के बाद इसे नेशनल हाईवे (एच-752डी) का दर्जा दिया गया था। अब यह मार्ग थांदला के टिमरवानी तक फोरलेन बन जाता है तो इसका नेशनल हाइवे की गिनती में आ जायेगा।

उद्योगों को मिलेगा लाभ

पश्चिमी मप्र सहित गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के तीर्थ यात्री इसी मार्ग से उज्जैन जाते हैं। अभी यह मार्ग बदनावर तक फोरलेन में तब्दील हो गया है। गुजरात की ओर से यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए इसे बदनावर से थांदला टिमरवानी तक भी फोरलेन में तब्दील करने की आवश्यकता है। इससे परिवहन के साथ ही माही नदी के उस पार के क्षेत्र में स्थापित हो रहे उद्योगों को दोहरा लाभ मिलेगा।

सत्यनारायण अग्रवाल व्यापारी

ये लाभ होंगे

इस मार्ग के पूर्ण होने के बाद दक्षिणी राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पूर्वी मध्य प्रदेश से गुजरात की तरह जाने वाला यातायात सुगम हो जाएगा। अभी इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरात जाते हैं। इसके निर्माण के बाद करीब 50 किमी की दूरी कम तय कर उज्जैन से बदनावर होते हुए या तो राजगढ़ में इंदौर अहमदाबाद मार्ग पकड़ सकेंगे या व्हाया पेटलावद और थांदला होकर जाएंगे तो दूरी और भी कम हो जाएगी।

मोहनलाल अग्रवाल व्यापारी

बदनावर से थांदला तक भी फोरलेन में तब्दील किए जाने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि थांदला के पास भी दिल्ली-मुंबई एट लेन से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। समीपस्थ धार जिले में माही नदी के उस पार छायन, दोत्रिया, तिलगारा, भैंसोला में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं। इसलिए इस मार्ग को फोर लेन बनाना अति आवश्यक था।

योगेंद्र सिंह राठौर पूर्व जनपद उपाध्यक्ष

ग्राम भैंसोला में तो करीब सात हजार करोड़ के निवेश से पीएम मित्र मेघा टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है। जिसमे लगभग 250 से ज्यादा उद्योग लगेंगे। इसमें निर्माण से लेकर निर्यात तक यहीं से होगा, इससे भी यातायात का दबाव बढ़ेगा। सरकार ने इसे फोर लाइन बनाकर आदिवासी बाहुल्य जिले के बाशिन्दों को रोजगार के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे।

अग्निनारायन सिह बोडायता भाजपा नेता।

पीएम मेघा टेक्सटाइल्स पार्क में 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, इस कारण यातायात का दबाव बढ़ना तय है। महाकाल लोक निर्माण के बाद भी करीब 40 प्रतिशत यातायात में वृद्धि हो गई है। साथ ही साल 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ के अवसर पर भी यह मार्ग अतिमहत्वूर्ण साबित होगा।

यश रामावत पटवारी राजस्व विभाग पेटलावद।

थांदला-बदनावर फोर लेन सड़क का सर्वे करते हुए

सारंगी चौपाटी पर ओवर ब्रिज बनेगा।

एक नजर में जानकारी

मार्ग की लंबाई- 86 किलोमीटर, रेल्वे ट्रेक- 01(दिल्ली मुम्बई), ओवर ब्रिज- 02 , 05 नदियों के कई जगह अंडर पास छोटे छोटे गाव के लिए।

सर्वे के बाद जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया

थांदला बदनावर टिमरवानी के बीच सर्वे हो रहा है, वही तीन बड़ी नदिया वागेड़ी नदी, माही नदी, लाढकी नदी, पम्पावती नदी, पद्मावती नदी के साथ दिल्ली मुम्बई रेलवे ट्रेक पर ब्रिज भी बनेंगा। साथी ही थांदला, पेटलावद और करड़ावद में बायपास एवं सारँगी चौपाटी पर ओवर ब्रिज के लिए सर्वे किया जा रहा है। सर्वे पूरा होने पर जमीन अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया होगी। इसमें कितनी राशि खर्च होगी, ये सर्वे के बाद पता चल सकेगा।

संदीप पाटीदार, प्रोजेक्ट ऑफिसर, एनएचएआई, रतलाम

संपादकीय

रडार पर पाकिस्तान

आखिरकार भारत की चिर-प्रतीक्षित मांग कि पाकिस्तान को आतंकवाद के पोषण के लिये कटघरे में खड़ा किया जाए, हकीकत बनती नजर आ रही है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद विश्व जनमत को पाकिस्तान की हकीकत बताने के जो सार्थक प्रयास किए थे, वे फलीभूत होते नजर आ रहे हैं। अब वैश्विक वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी एफएटीएफ, जो मनी लॉन्निंड्रग और आतंकवाद के वित्तपोषण गतिविधियों के लिए वैश्विक निगरानी संस्था है, ने अंततः 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की है। एफएटीएफ ने भारत की तार्किक दलील पर ही मोहर लगायी है। एफएटीएफ ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि 'ऐसे घटनाक्रम बिना पैसे और आतंकवादियों के समर्थकों के बीच फंडों के स्थानांतरित करने के बगैर नहीं हो सकते।' आतंकवाद के लिए फंडिंग के रिकॉर्ड की निगरानी करने वाली इस संस्था ने फरवरी 2019 में पुलवामा आत्मघाती हमले की भी निंदा करते हुए ऐसे ही शब्दों का उपयोग किया था। लेकिन इस बार का अंतर यह है कि एफएटीएफ ने घोषणा की है कि 'राज्य प्रायोजित आतंकवाद' इसकी आगामी रिपोर्ट में आतंकवाद के वित्तपोषण मामलों की जांच का हिस्सा होगा। दरअसल, पहलगाम नरसंहार के बाद भारत लगातार पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग करता रहा है। जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय ऋणों तक पहुंच को गंभीर रूप से सीमित कर देगा। उल्लेखनीय है कि पाक को वर्ष 2022 में इस सूची से हटा दिया गया था। दरअसल, पाकिस्तान गढ़े हुए तर्कों के आधार पर इस निगरानी संगठन को मनाने में सफल रहा था कि वह धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने के लिये अपने सिस्टम में सुधार कर रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रबल विरोध के बावजूद इस्लामाबाद ने अंतर्राष्ट्रीय मद्रा कोष यानी आईएमएफ से एक अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। हालांकि, इस बेलआउट पैकेज के साथ कई कड़ी शर्तों का सामना भी पाकिस्तान को करना पड़ेगा।

यह विडंबना ही कि पश्चिमी देश अपने स्वार्थों के लिये आतंकवाद पोषण की परिभाषा ही बदल देते हैं। उन्हें मानवता के प्रति अपराध करने वाले देश अपने निहित स्वार्थों के चलते पाक-साफ नजर आने लगते हैं। भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी तब हैरान हुई जब आईएमएफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिये संतोषजनक प्रगति की है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने बेनकाब किया। भारत ने दुनिया को बताया कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद की पाठशालाओं को स्वास्थ्य केंद्रों या स्कूलों के रूप में छिपा रहा था। पाकिस्तान का मकसद था कि इससे दुनिया को आतंकवाद के प्रशिक्षण केंद्रों का पता नहीं चलेगा और वह वैश्विक संगठनों की सजा से बच जाएगा। दरअसल, पाकिस्तानी हुकमरान हमेशा से खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मदद हासिल करने की फिराक में रहते हैं। भारत ने इस खतरे का हवाला देते हुए विश्व जनमत को हकीकत से अवगत कराने का प्रयास किया है। अब यह एफएटीएफ के कर्ता-धर्ताओं के विवेक पर निर्भर करता है कि वे पाक के खतरनाक मंसूबों को कितनी जल्दी भांपने में कामयाब हो सकते हैं। एक ओर पाकिस्तान आर्थिक बदहाली का हवाला देकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी ओर उसने अपनी रक्षा मद पर बीस प्रतिशत व्यय बढ़ा दिया है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान इस रक्षा बजट वृद्धि का सारा पैसा राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च नहीं करेगा। धन के किसी भी दुरुपयोग का पता लगाने के लिये उसके नियमित खर्च की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को करनी चाहिए। भारत को निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह आतंकवादी हमलों को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क को खत्म करने के पाकिस्तान के दावे की हकीकत पता लगाए। अब वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी एफएटीएफ को इस बात पर जोर देना चाहिए कि पाकिस्तान की कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित हो ताकि पाकिस्तान एक बार फिर से अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम न दे सके।

सैनिक परंपरा में मौजूद कर्तव्य परायणता का संकल्प

जन.एस.एस. मेहता

भारत की वीर परंपरा, किसी साम्राज्य द्वारा गढ़ी गयी नहीं, बल्कि इसे स्थाई शासकों और हमले रोकने वाले महानायकों द्वारा आकार दिया गयादृकुछ वे जिन्होंने दशकों तक राज्यों का निर्माण किया, और वे भी जो थोड़े समय के लिए राजा रहे, लेकिन साहस और विवेक के अडिग प्रहरी बन खड़े रहे। रणनीतिक एकीकरण-कर्ता चंद्रगुप्त से लेकर गुरिल्ला युद्ध के महानायक शिवाजी; संत-सिपाही गुरु गोबिंद सिंह, रॉकेट तकनीक के अग्रणी टीपू सुल्तान, असम के प्रहरी लाचित बोरफुकन, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई; सीमांत सिंह हरिसिंह नलवा, योद्धा राजा राणा सांगा, रणनीतिकार महाराजा सूरजमल, विद्रोही वीरपांड्या कट्टाबोमन, नैतिक परिवर्तनकर्ता अशोक, समन्वयवाद के अगुआ अकबर, त्वरित रणनीतिकार बाजी राव, दक्षिण के प्रहरी कृष्णदेवराय,वर्दीधारी देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक।

ये नाम बानगीभर हैं - देश के सभी भागों से, धर्मों, भाषाओं और सदियों से आते हैं। ये काल्पनिक पात्र नहीं, चरित्रवान योद्धा थेदृ लूटने की बजाय सम्मान, अधीन करने की जगह न्याय देना, विरासत लूटना नहीं बल्कि बनाना उनका गुण था। भारत के योद्धा कभी भी धन से या विजयों से गढ़े हुए नहीं रहे। वे एक सभ्यतागत विरासत का उत्पाद हैं- साम्राज्यों से भी पुराना, सिद्धांत से भी गहरा, भाड़े के सैनिकों की सोच से इतर। जबकि अनेक उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्रों को शाही सेनाएं विरासत में मिलीं, भारतीय फौजी युद्ध के मैदान में कुछ और लेकर उतरता है- नाम (सम्मान), नमक (कर्तव्य) और निशान (ध्वज) की सेवा के प्रति असीम दायित्व का संकल्प। यह ब्रिटिश उपहार नहीं, हमारी विरासत है।

वह जो ब्रिटिश साम्राज्य जीत नहीं पाया- अंग्रेजों ने अपना झंडा भले फहराया हो। लेकिन वे हमारी आत्मा कभी नहीं जीत पाए। भारतीय सैनिक विदेशी झंडे के नीचे जरूर लड़े लेकिन साम्राज्य के लिए नहीं। वे पलटन, इज्जत और विरासत की खातिर लड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरदस्ती भर्ती तो कर ली, लेकिन आत्मसम्मान की ज्वाला बुझा नहीं पाए। विदेशी युद्धों में भी भारतीय सैनिक शाही आदेश का नहीं बल्कि आंतरिक संहिता का पालन करते थे। युद्ध सम्मान शाही पुरस्कार न होकर नैतिकता के प्रमाण थे। झंडा भले विदेशी रहा, निष्ठा सदा भारतीय रही।

1971-विवेकपूर्ण कमान- भारत ने लाभ की खातिर पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं किया। नरसंहार खत्म करने को सीमा पार की। केवल 13 दिनों में, भारतीय सेना ने एक राष्ट्र आजाद कराया - और वापस लौट आई। लूटपाट नहीं की, कठपुतली सरकार नहीं बनाई। कोई विलय नहीं। यह कुरुक्षेत्र की पुनरावृत्ति थी- संयम से लड़ा गया न्यायपूर्ण युद्ध। यह 20वीं सदी में दुनिया का सबसे नैतिकतापूर्ण सैन्य दखल था- अभियान जो सिर्फ रणनीति से नहीं, विवेक से संचालित हुआ।

कारगिल- एक संकल्प की पुष्टि- कारगिल (1999) ने राजनीतिक और क्षेत्रीय संयम के तहत सामरिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया दृतीखी चढ़ाई की बाधाओं के खिलाफ लड़ते हुए, फिर भी नियंत्रण रेखा पार नहीं की। युवा अधिकारी और सैनिक बर्फीली चट्टानों पर चढ़ निकले, यह जानते हुए भी कि फिर कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। वे पदकों या सुर्खियां बटोरने नहीं, पलटन व झंडे के लिए गए। जहां कुछ फौजी पूछेंगे- इसमें मेरे लिए क्या है'?, हमारे बहादुर युवा अधिकारी कह रहे थे- ये दिल मांगे मोर'।

ऑपरेशन सिंदूर- संयम ही बल है- हाल में, जब भारत की खींची लक्ष्मण रेखाएं पार की गईं, तब जवाब दिया गया - आवेश में नहीं, बल्कि सावधानी भरी सटीकता से। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के रुख की पुष्टि की- सैनिक न तो छोटी बात पर भड़कता है और न ही व्यर्थ के उकसावे पर। यह लड़ाई, युद्ध से पहले ही जीत ली गई। यह क्रूर बल नहीं, क्रमिक विकास की ताकत है। उकसावे पर उद्देश्य को महत्त्व।

सैन्य साजो सामान और सम्मान में फर्क-बजट, ड्रोन, एआई - इनमें से कोई भी परंपरा नामक बल-गुणक को नहीं माप सकता। सैनिक इनाम-उपहार के लिए नहीं बल्कि विरासत बनाए रखने के लिए जान की बाजी लगाता है। सुनिश्चित करने को कि सम्मान की कड़ी कभी न टूटे। वह सम्मान बनाए रखना चाहता है। इसके लिए, वह हमेशा तैयार रहता है। असीमित दायित्व कोई अस्थाई मद नहीं, नैतिक स्थिरांक है। वह ये नहीं पूछता, 'मुझे क्या मिलेगा'? बल्कि पूछता है, 'मुझे क्या देना होगा'?

जिम्मेदारी- सैनिक परंपरा का दूसरा पहलू- लेकिन यह एकतरफा संकल्प नहीं। सैनिक को भी वर्दी की इज्जत बनाए रखनी चाहिए। जब वह अपनी सुरक्षा के बदले चुप्पी, सत्य की बजाय फायदा चुने या नौकरी बचाने की खातिर कर्तव्य का सौदा करे - तो वह हारने से कहीं अधिक कर बैठता है। नैतिक मूल्य खंडित कर देता है। सैनिक की महानता केवल युद्ध लड़ने में नहीं, बल्कि क्षरण का विरोध करने में है दृसाहस, विवेक और स्पष्टता का ह्रास होता देखकर। युद्ध सीमा पर खत्म नहीं होता, निर्णयों, फाइलों और सच्चाई में जारी रहता है।

हर और मचता शोर- हर युद्ध के बाद शोर मचता है- 'टैंकों का दौर चला गया। मानव चालित विमान पुराने पड़ गए। अब राज ड्रोन का है। विमान वाहक पोत का जमाना लद गया। तोपखाने का क्या काम, साइबर ही सब कुछ है।' लेकिन सच्चाई कायम रहेगी- सैनिक जिंदा है। युद्ध के तौर-तरीके वक्त के साथ विकसित होते रहते हैं। सैन्य उपकरण व एल्गोरिद?म विफल हो सकता है। लेकिन सैनिक कायम रहेगा- एकमात्र हथियार प्रणाली जो खुद सोच सके,खुद को ढाल सकता है, नेतृत्व कर सके और बड़े उद्देश्य के लिए जान दे सकता है। बाकी सब कुछ नष्ट होने की संभावना है। सैनिक का कोई तोड़ नहीं।

कोहिमा संदेश- 'जब तुम घर जाओगे, उन्हें हमारे बारे में बताना और संदेश देना- तुम्हारे कल के लिए, हमने अपना आज दिया।' यह संदेश मृतकों के लिए नहीं,जीवितों के लिए है। इसमें यदि आगे जोड़ा जाए-'और याद रखोः एक राष्ट्र की आत्मा फाइलों में नहीं होती, बल्कि उन लोगों द्वारा धारण की जाती है, जो दूसरों के मुंह फेर लेने के बाद आग में होम होना चुनते हैं'। एक जीते-जागते लोकतंत्र में, सैनिक की असली शक्ति संयम में है। उसका मौन समर्पण नहीं बल्कि शक्ति है। अराजनीतिक बने रहना उदासीनता नहीं, अनुशासन है। भारतीय सैनिक विचारधारा को नहीं, संविधान को सलाम करता है। ऐसा करके वह राष्ट्र को याद दिलाता है कि लोकतंत्र की बेहतरीन रक्षा पक्षपात से नहीं, सिद्धांतों से होती है। हर वह युद्ध जो भारत को लड़ने पर मजबूर किया गया, उसमें न केवल वह हावी रहा दृबल्कि लोकतंत्र ने सैन्य शासन को परास्त किया, भारतीय सैनिक की मानवता ने पाकिस्तानी बर्बरता को मात दी। 1971 से लेकर कारगिल और ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय सैनिक ने दिखाया कि जब शक्ति प्रदर्शन लोगों की खातिर होता है, तो वह बेजोड़ होता है।

और अब ब्रिटेन के अपने शब्दों में- अब दशकों बाद, ब्रिटिश लोग स्वीकार कर रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में उनका बेहतरीन सैन्य अभियान यूरोप या उत्तरी अफ्रीका में नहीं - बल्कि बर्मा में था। यूके के राष्ट्रीय सेना संग्रहालय द्वारा 2013 में किए गए एक सर्वेक्षण में, इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयों को डी-डे (जिस रोज जर्मनी पर निर्णायक संयुक्त हमला किया) और वाटरलू युद्ध से पूर्व ब्रिटेन की महानतम लड़ाइयों के रूप में चुना गया। इम्फाल और कोहिमा में - कीचड़, मलेरिया और भुखमरी के बीच- भारत के सैनिक अपनी लीक पर कायम रहे और रुख मोड़ दिया। ये लड़ाइयां, जिन्हें ब्रितानी साम्राज्य के युद्ध विजय खाते से बाहर रखा गया था, आज इन युद्धों को धीरज, अनुशासन और बलिदान के महाकाव्यों के रूप में फिर पढ़ा जा रहा है दृ वे गुण जो साम्राज्य के नहीं, बल्कि उन लोगों के हैं, जिन्होंने साम्राज्य को उसका अंतिम नैतिक आधार दिया।

सैनिक की विरासत- वह जो सहस्राब्दियों तक कायम रही। निष्ठा से गढ़ी हुई। असीमित दायित्व से बंधी। विविधता में एकता से मजबूत हुई। नाम, नमक, निशान से प्रेरित। और जब अवसर आता है - कोई धूमधाम नहीं, प्रतिध्वनि नहीं। बस कर्तव्य निभाना है। उस झंडे की सेवा में जिसका वह सम्मान करते हैं, वह फौज जिसने उन्हें आकार दिया, वह फौजी यूनिट जो उनका घर है, और अपने साथी सैनिक की खातिर- जब भी ज़रूरत पड़े, जान न्योच्छावर कर देना। उनकी शपथ गणतंत्र के प्रति है - सदैव, और हर बार।

साइप्रस से कुटनीतिक- आर्थिक संबंधो के हितार्थ

पुष्परंजन

अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दक्षिणी दिल्ली की उस सड़क के नाम को सुधारा जायेगा। लोधी रोड के पीछे, पेड़ों से घिरा एक छोटा-सा रास्ता, जहां हरे रंग के एक बोर्ड पर हिंदी में लिखा है- 'आर्च बिशप माकोरियस मार्ग'। अंग्रेजी, गुरुमुखी, और उर्दू में भी वही लिखा है। दिल्ली स्थित साइप्रस उच्चायोग वालों का भी ध्यान दशकों से लगे इस बोर्ड पर नहीं गया। वास्तविक नाम है- 'आर्चबिशप मकारियोस तृतीय।' प्रधानमंत्री मोदी से पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस सर्वोच्च सम्मान से नवाज़े जा चुके हैं। वर्ष 2017 में उन्हें यह पुरस्कार, साइप्रस की यात्रा के दौरान मिला, जहां उन्होंने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादेस से मुलाकात की। यह पुरस्कार भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया था।

वर्ष 2017 में साइप्रस गणराज्य ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का समर्थन किया। मगर, मकारियोस तृतीय के वास्तविक नाम से आठ साल तक दिल्ली वाले अनजान रहे। प्रधानमंत्री मोदी को मिले पुरस्कार पर भी उनका नाम है, जिसने निकोसिया और नई दिल्ली के बीच एक ऐतिहासिक सूत्र को मजबूत किया था। वर्ष 1983 में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में कई महत्वपूर्ण नेता आए थे, तब मुझे भी विदेश मंत्रालय में बहैसियत 'प्रोटोकॉल असिस्टेंट', काम करने का अवसर मिला था। दिल्ली आये जिन नेताओं को तब नज़दीक से देखने का अवसर मिला था, उनमें फिदेल कास्त्रो, यासिर अराफात भी शामिल थे। इसके बाद, कुछ चुनिंदा सड़कों को गुटनिरपेक्ष नेताओं के नाम रखा गया- 'जोसिप ब्रोज टीटो मार्ग, गमाल अब्देल नासर मार्ग, हो ची मिन्ह मार्ग- और 'माकोरियस मार्ग'।

मकारियोस के नाम पर यह सड़क उस कूटनीतिक युग का अवशेष है, जो कभी बहुत चमकता था। बाद के दिनों में मनमोहन सरकार ने आर्चबिशप मकारियोस तृतीय की स्मृति में डाक टिकट जारी किया था। अब अचानक से आर्चबिशप मकारियोस तृतीय भारत में वायरल हो गए, जिन्होंने 1950 से 1977 तक साइप्रस के चर्च के आर्च बिशप के रूप में और 1960 और जुलाई, 1974 के बीच साइप्रस के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उसके प्रकारांतर, दिसंबर, 1974 और 1977 के बीच दूसरे कार्यकाल में भी वो शासन प्रमुख बने रहे। उन्हें साइप्रस गणराज्य के संस्थापक पिता, 'एथनार्क' के रूप में माना जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से इसके हस्तांतरण का नेतृत्व किया था। हालांकि, ब्रिटिश सरकार इस द्वीप को उपनिवेश मुक्त करने के लिए अनिच्छुक थी। ब्रिटिश गए भी, तो साइप्रस को भारत-पाकिस्तान की तरह बांटकर, और विवाद को रोपकर।

ईओकेए बी एक ग्रीक साइप्रस अर्धसैनिक संगठन था, जिसे 1971 में जनरल जॉर्जियोस ग्रिवास ने अति राष्ट्रवादी विचारधाराओं के आधार पर बनाया था। इस संगठन का उद्देश्य साइप्रस को ग्रीस के साथ एकीकृत करना था, लेकिन बाद में नागरिकों पर हमलों के परिणामस्वरूप, साइप्रस गणराज्य द्वारा इसे गैरकानूनी घोषित कर, एक आपराधिक संगठन माना गया था।

आर्च बिशप मकारियोस एकमात्र यूरोपीय नेता थे, जिन्होंने अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित उपनिवेशवाद विरोधी 'बांडुंग सम्मेलन' में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काम किया था। यह वह सम्मेलन था, जिसने अंततः गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, जो अमेरिका और यूएसएसआर के नेतृत्व वाले शीतयुद्धीय शिविरों का विकल्प था। साइप्रस बेलग्रेड में 1961 के गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में पच्चीस प्रतिभागियों में से एक था, जिसने औपचारिक रूप से आंदोलन की स्थापना की। 1957 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, भारत के विदेश मंत्री कृष्ण मेनन साइप्रस की स्वतंत्रता के पहले अधिवक्ताओं में से एक थे। मेनन ने साइप्रस की बिना शर्त स्वतंत्रता की वकालत की। आज, साइप्रस संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ का सदस्य राज्य है। तुर्की का प्रतिद्वंद्वी, जो सारे घोड़े खोल लेने के बाद भी यूरोपीय संघ का सदस्य देश नहीं बन सका। साइप्रस 1 मई, 2004 को यूरोपीय संघ का सदस्य देश बना, 2026 में उसे ईयू का अध्यक्ष देश बनना है। इससे पहले 2012 में साइप्रस ईयू का अध्यक्ष देश बना था।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जून, 2025 को ग्रीक-साइप्रस संबंधों को और गहरा करने का संकल्प लिया। उन्हें इस साल के अंत तक यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। ज़ाहिर है, जब साइप्रस यूरोपीय संघ का अध्यक्ष देश बनेगा, भारत से संबंधों की नई इबारत लिखी जाएगी। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा गश्त की जाने वाली उस ग्रीन लाइन का भी दौरा किया, जो राजधानी निकोसिया को दो भागों में विभाजित करती है। यह एदोंआन को अखर रही होगी।

सम्भव है, साइप्रस अगला टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, कि अंकारा द्वारा इस्लामाबाद का समर्थन करने के बाद, तुर्की में भारतीय पर्यटकों की आमद में कमी आई थी, साथ ही भारतीयों ने तुर्की के उत्पादों और सेवाओं का भी बहिष्कार किया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की के ग्राउंड सर्विस प्रदाता सेलेबी के लिए सुरक्षा मंजूरी भी रद्द कर दी। भारत और साइप्रस के दोनों शिखर नेताओं ने सीमा पार लेन-देन के लिए साइप्रस में यूपीआई सेवाएं शुरू करने, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और साइप्रस के यूरोबैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन की सुविधा प्रदान की। भारत, ऊर्जा-तकनीकी सहकार के साथ-साथ मध्य पूर्व-यूरोप व्यापार गलियारे को डेवलप करने के लिए प्रयासरत है, जो चीन का 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' का विकल्प बन सकता है।

फिर भी, निकोसिया और नई दिल्ली के दिल मिलाने के प्रयास काफी करने होंगे। अव्वल, आम भारतीय साइप्रस के मैरोनाइट ईसाई, अर्मेनियाई, और कुछ हज़ार अरबी भाषियों के स्वभाव, खान-पान, संगीत-संस्कृति से अनजान है। यह ग्रीस के दक्षिण-पूर्व में, तुर्की के दक्षिण में, सीरिया और लेबनान के पश्चिम में, इस्राइल- फलस्तीन के उत्तरपश्चिम में, और मिस्र के उत्तर में अवस्थित, साढ़े नौ हज़ार वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला देश है। 'तुर्की का कट्टर दुश्मन, भारत का पक्का दोस्त...।' जैसे टेलीविजनी हेडलाइंस सुनने में अच्छे तो लगते हैं, लेकिन लगभग त्रिपुरा के साइज़ के इस छोटे से देश को तुर्किये के मुक़ाबले टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम बना दें, खान-पान, संगीत हमें रात भर में रुचिकर लगने लगे, ये सब हवा-हवाई बातें हैं। साइप्रस के कवि और लेखक, प्रोफेसर स्टेफानोस स्टेफनाइड्स को हिंदी साहित्य का विद्यार्थी कितना जानता है? भारतीय प्रकाशन द्वारा उनकी अनुदित कविता अद्भुत है, 'हम सभी का वध करो, और हमारे खून को नदी बना दो...।'

हनीट्रेप गिरोह का पर्दाफाश, आरक्षक से दो लाा रुपये वसूले

माही की गूंज, मंदसौर।

मंदसौर नगर में हनी ट्रैप का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव लूनाहेड़ा निवासी एक महिला और उसके कथित पति ने पुलिस आरक्षक से बलात्कार के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठ ली। पुलिस ने दोनों को आरोपित बनाते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

38 वर्षीय आरक्षक गोपाल मालवीयए जो वर्तमान में नीमच में पदस्थ हैंए ने बताया कि गांव की ही रंजू नामक महिला ने घरेलू विवाद के बाद उसे 16 जनवरी 2024 को अपने घर बुलाया था। बातचीत के दौरान रंजू का पति हरीश तिवारी अचानक वहां पहुंचा और गोपाल पर गलत आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगा। इसके बाद दंपती ने मिलकर धमकी दी कि अगर रुपये नहीं दिए गए तो बलात्कार के झूठे केस में फंसा देंगे। इस धमकी के बाद दोनों ने 10 लाख रुपये की मांग कीए जो बाद में चार लाख रुपये पर तय हुई।

पीड़ित आरक्षक ने किसी तरह दो लाख रुपये की व्यवस्था की। 12 अप्रैल को एक लाख रुपये नकद दिए गए और उसका वीडियो भी बनाया गया। उसी दिन एक लिखित समझौता भी कराया गया। इसके बाद 70 हजार रुपये और किस्तों में मोबाइल से भेजे गए। बावजूद इसकेए महिला द्वारा इंटरनेट पर धमकी देना और पैसों की मांग करना जारी रही।

पुलिस ने इस मामले में रंजू और उसके पति हरीश तिवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 308(6), 61 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि उक्त महिला पूर्व में भी कई लोगों से इसी तरह की वसूली कर चुकी है। हालांकिए लोकलाज के कारण अन्य पीड़ित सामने नहीं आ रहे हैं।

कोर्ट बना रणभूमि, भरण-पोषण के मामले में भिड़े दो पक्ष

माही की गूंज, रतलाम।

शहर के एसडीएम कार्यालय परिसर में सोमवार को उस समय हंगामा मच गयाए जब एक पारिवारिक विवाद की सुनवाई के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। यह मामला एक बुजुर्ग महिला रतनबाई के भरण.पोषण से जुड़ा हुआ है।

जानकारी के अनुसारए रतनबाई का पालन.पोषण वर्तमान में उनका पोता और बहू कर रहे हैं। जबकि रतनबाई ने अपने ही दोनों बेटों के खिलाफ भरण.पोषण का प्रकरण उपखण्ड दंडाधिकारी न्यायालय में दायर कर रखा है। सोमवार को जब दोनों पक्ष सुनवाई के लिए कोर्ट में पहुंचे तो कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट तक जा पहुंचा। देखते ही देखते परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मारपीट होते देख मौके पर मौजूद लोगों ने बीच.बचाव कर किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया।

इस पूरी घटना का एक दृश्य किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर लियाए जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद से यह मामला शहरभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि घटना के वक्त उपखण्ड दंडाधिकारी अनिल भाना न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कहा है कि कोर्ट परिसर में हुई इस घटना की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी करते पकड़े गए तीन युवक, ग्रामीणों ने की पिटाई

माही की गूंजए मंदसौर।

सीतामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम सेमलिया रानी में ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी करते तीन युवकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने तीनों युवकों के कपड़े उतरवाकर उनकी जमकर पिटाई की और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तीनों युवकों को गिरफ्तार कर विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए युवकों के साथ मारपीट कीए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने बताया कि सेमलिया रानी गांव की यह घटना ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी से जुड़ी है। आरोपित युवकों पर पूर्व में भी इसी तरह की चोरी के मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस मामले में दोनों पक्षों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

मोबाइल चोरी या गुम होने पर तुरंत होगा ट्रैक

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम जिले में मोबाइल चोरी या गुम होने की स्थिति में अब तुरंत पता लगाने की सुविधा उपलब्ध हो गई हैए जिससे आम लोगों को मोबाइल रिकवरी में बड़ी आसानी होगी और चोरी के मामलों में भी पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सकेगी। भारत सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल को जिले के सभी थानों में लागू कर दिया गया हैए जिससे अब मोबाइल चोरी या गुम होने की शिकायत दर्ज कराने के लिए साइबर सेल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह पोर्टल आपके मोबाइल के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या के आधार पर कार्य करता है और चोरी या खोए हुए मोबाइल को तुरंत अवरुद्ध कर देता है ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके। जब कोई व्यक्ति आपके चोरी हुए मोबाइल में नई सिम लगाता है और फोन चालू करता हैए तो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक सूचना संदेश भेजा जाता हैए जिससे आपको पता चल जाता है और आप पुलिस को सूचित कर आगे की कार्रवाई करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी सरल हैए जिसमें पहले नजदीकी थाने में जाकर मोबाइल चोरी या गुम होने की शिकायत दर्ज करनी होती है और उसकी एक प्रति प्राप्त करनी होती है। इसके बाद मोबाइल सेवा प्रदाता को कॉल कर सिम को अस्थायी रूप से बंद कराया जाता है। फिर आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवश्यक जानकारी भरकर अपने मोबाइल को अवरुद्ध करवा सकते हैं और एक अनुरोध पहचान संख्या प्राप्त करते हैंए जिससे अपनी शिकायत की स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं।

पुलिसकर्मियों को इस प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और बीते एक महीने में रतलाम के थानों से करीब 75 शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी हैं। यह सेवा मई 2023 से पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और अब रतलाम में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इससे न केवल मोबाइल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद बढ़ी हैए बल्कि खोए हुए मोबाइल की प्राप्ति की संभावनाएं भी बेहतर हुई हैं। इसके अलावाए यह एक उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रणाली हैए जिससे आम जनता भी आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और मोबाइल की स्थिति पर नजर रख सकती है। इससे मोबाइल चोरी से जुड़ी अपराध प्रवृत्ति में कमी आने की भी संभावना जताई जा रही हैए जिससे लोगों को अपनी सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा मिलेगा।

निर्माणाधीन कुआं धंसने से दो मजदूरों की मौत

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के जावरा क्षेत्र के जूना गडगडिया गांव में मंगलवार शाम एक निर्माणाधीन कुआं धंसने से दो मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब 40 फीट गहरे कुएं की दीवार का निर्माण कार्य किया जा रहा था। जावरा के नगर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश आर्मो ने बताया कि दिनभर हुई रिमझिम बारिश से मिट्टी गीली हो गई थीए जिससे कुएं की दीवार भरभराकर गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम राहत कार्यों में जुट गई। करीब साढ़े छह घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात डेढ़ बजे के बाद दोनों शव मलबे से निकाले गए। मृतकों की पहचान केलुखेड़ा गांव निवासी विक्रम सिंह ;43द्ध और अमर सिंह ;32द्ध के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को शव परिजनों को सौंप दिए गए।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर होगा जिला स्तरीय योग कार्यक्रम

माही की गूंज, मंदसौर।

आगामी 21 जून को 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसके आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर अदिति गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम संजय गांधी उद्यान एवं पशुपतिनाथ मंदिर के आराधना हाल में आयोजित किए जाएंगे।

सभी विभाग योगा संगम ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। साथ हीए जो भी प्रतिभागी योग अभ्यास कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैंए वे भी इस ऐप के जरिए पंजीयन करा सकते हैं। जन अभियान परिषद को इसका व्यापक प्रचार.प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर पालिका को संजय गांधी उद्यान एवं पशुपतिनाथ मंदिर हाल में साफ.सफाईए प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान आरोग्य केन्द्रों पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतोंए जनपद पंचायतोंए नगरीय निकायों तथा जिला स्तर पर भी पृथक.पृथक कार्यक्रम आयोजित होंगे। 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वीए एक स्वास्थ्य की थीम पर आधारित हैए जिसमें पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सामूहिक रूप से योग किया जाएगा।

योग भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति की अमूल्य देन हैए जो आज संपूर्ण विश्व को आरोग्यता और संतुलन की दिशा में प्रेरित कर रही है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुकूल जैनए आयुष विभाग के अधिकारीए एसडीएम एवं विभिन्न योग संस्थाओं के प्रमुख उपस्थित रहे।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

माही की गूंज, शाजापुर।

शाजापुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी बद्रीलाल (22 वर्ष) को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया है।

यह मामला 7 जनवरी 2021 का है। पीड़िता के भाई ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन रात में घर से गायब हो गई है। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता को इंदौर के भांग्या स्थित एक ईंट भट्ठे से बरामद किया। वहां वह आरोपी बद्रीलाल के साथ मिली। पीड़िता ने बताया कि 6 जनवरी 2021 की रात बद्रीलाल उसे बहला.फुसलाकर जबरन इंदौर ले गया। रास्ते में उसका मुंह कपड़े से ढंककर सारंगपुर बस स्टैंड तक ले गया। वहां से इंदौर पहुंचकर उसे भट्ठे की झोपड़ी में रातभर रखा और दुष्कर्म किया। अगले दिन उज्जैन ले जाकर एक किराए के मकान में फिर दुष्कर्म किया गया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी ने मामले में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376;2द्ध;एनद्ध के तहत दोषी करार दिया। पुलिस ने इस प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया।

पत्नी ने की दूसरी शादी तो आगबबूला हुआ पहला पति

माही की गूंज, शाजापुर।

शाजापुर जिले के ग्राम चन्दानी में एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यह घटना 16 जून 2025 की रात लगभग 10 बजे की है।

ग्राम भेंसोदा निवासी किसान के बेटे संजय ने पूजा नामक युवती से विवाह किया। पूजा की पहली शादी ग्राम कडुला के निवासी लालजीराम से हुई थी। बताया जा रहा है कि लालजीराम ने 7 जून को पीड़ित के बड़े बेटे को और 8 जून को स्वयं पीड़ित को फोन कर पूजा से दूसरी शादी न होने का दावा करते हुए झगड़े के पैसे की मांग की। साथ ही धमकी दी कि पैसे नहीं देने पर गंभीर नुकसान करेगा।

16 जून की रात को जब पीड़ित व्यक्ति अपने खेत के कुएं पर सो रहे थेए तभी लालजीराम मोटर साइकिल से आया और खेत में रखे भूसे के ढेर में आग लगा दी। इसके बाद पास बनी परमानंद की झोपड़ी में भी आग लगा दी। आग की रोशनी में पीड़ित ने लालजीराम को पहचान लिया।

इस घटना में पीड़ित के लगभग 45 बीघा गेहूं का भूसा जल गयाए जिससे लगभग 12 हजार रुपये का नुकसान हुआ। वहीं परमानंद की झोपड़ी में रखे खाटए बिस्तरए पाइप और केबल जलने से करीब 20 हजार रुपये का नुकसान हुआ।

मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी वामन किशोर व्यास के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

राष्ट्रीय पक्षी मोर को मयूर वन में बसाना था.. लेकिन भूले

माही की गूंज, उज्जैन।

राष्ट्रीय पक्षी मोर कोठी तथा विश्व विद्यालय परिसर के आसपास बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। वहीं ग्राम मंगरोला फिलहाल उज्जैन में मोरों का गढ़ है। गर्मी के दिनों में इनके दाना-पानी की आपूर्ति भगवान भरोसे हो रही है, क्योंकि वन विभाग के पास इसकी व्यवस्था के लिए बजट नहीं है। वहीं मोरों के संरक्षण के लिए लाखों खर्च कर बनाया गया मयूर वन भी उनके काम नहीं आ रहा।

उल्लेखनीय है कि, उज्जैन शहर में कोठी पैलेस तथा विश्वविद्यालय परिसर में अभी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पक्षी मोर नजर आते हैं। इसके अलावा 6 साल पहले तक हीरामिल और विनोद मिल परिसर में भी सैकड़ों की संख्या में मोर रहते थे। परंतु यहां स्मार्ट सड़क बनने के बाद इनके आशियाने उजड़ गए थे। इसके बाद से इस क्षेत्र से मोरों की प्रजाति विलुप्त हो गई है। वहीं उज्जैन के मंगरोला गांव में आज भी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पक्षी मोर बसे हुए है। गाँव में 600 के लगभग मोर रहते है। शर्मीले और डरपोक स्वभाव वाले मोर अब मंगरोला गाँव का हिस्सा बन चुके है। जिस तरह घर में पालतू जानवर श्वान या बिल्ली नजर आती है उसी तरह अब गाँव के कई घर और छतो पर मोर नजर आते हैं। इनके संरक्षण के लिए गाँव के ही कुछ युवाओ ने मोर सरंक्षण केंद्र बनाया है, जिसमें मोरो के लिए उपचार और रहने के लिए जगह बनाई है। इसके साथ ही रोज दाना पानी की भी व्यवस्था की गई है। जबकि कोठी तथा विश्वविद्यालय परिसर और अन्य स्थानों पर पाए जाने वाले मोर की देखरेख और विशेषकर गर्मी में दाना-पानी की व्यवस्था के लिए वन विभाग द्वारा कोई इंतजाम नहीं किए जाते। वन विभाग से जुड़े अधिकारी सूत्रों का कहना है कि विभाग के पास मोर के संरक्षण और उनके दाना-पानी की व्यवस्था के लिए अलग से कोई बजट नहीं है। इधर शहरी क्षेत्र में दाना पानी की तलाश में आए मोर कई बार करंट का शिकार हो जाते हैं। जिससे उनकी जान चली जाती है। इस प्रकार से मोरों को कुत्तों व करंट से बचाने के लिए प्रयास किए जाना जरूरी है।

बस नाम का रह गया मयूर वन

मयूर वन प्रोजेक्ट के तहत 1 करोड़ की अधिक की लागत से साल 2018 से इसके निर्माण का काम शुरु किया गया था। योजना के मुताबिक पार्क को मोर के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना तथा उसका संवर्धन करना था। इसके अलावा यहां मनोरंजन के लिए भूल भूलैया भी बनाई गई है। वाटिका के तालाब को सुंदर तालाब में तब्दील कर दिया गया है लेकिन हालत यह है कि मयूर वन में मोरों को बसाने और इनके संरक्षण के कोई प्रयास नहीं किए गए है।

भगवान चित्रगुप्त पर टिप्पणी को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने मांगी माफी

सीहोर।

कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। महाराष्ट्र में कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त पर की गई उनकी टिप्पणी को लेकर कायस्थ समाज ने तीखा विरोध जताया, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगते हुए कहा, ÷मेरे किसी कथन से यदि किसी समाज या व्यक्ति को ठेस पहुंची हो या उनका मन दुखा हो, तो मैं क्षमा मांगता हूं।÷

जानकारी के अनुसार, मिश्रा ने कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त के बारे में कथित तौर पर 'अभद्र भाषा' का उपयोग किया था, जिसके बाद कई शहरों में विरोध शुरू हो गया। कई साधु-संतों और कथावाचकों ने भी उनके बयान की निंदा की थी।

बार-बार ऐसी गलतियां दोहराने पर सवाल किए जाने पर पंडित मिश्रा ने कहा, ÷मैं वही कहता हूं जो शास्त्रों में लिखा है. सबका कहने का तरीका अलग होता है। हो सकता है मेरा तरीका कुछ अलग हो, जिससे लोगों का मन दुख जाता हो। इसके लिए मैं सभी से क्षमा मांगता हूं।÷ फिलहाल लगातार हो रहे विरोध के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह माफी मांगी है।

मुख्यमंत्री आज करेंगे 266 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण

माही की गूंज, खरगोन।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज खरगोन जिले के बेड़िया पहुंचेंगे। वे दोपहर 3ः10 बजे मिर्च मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां 266 करोड़ 64 लाख रुपये लागत के 24 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सिकलसेल दिवस के अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में मुख्यमंत्री सिकलसेल पीड़ित मरीजों को प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। इसी कार्यक्रम में वे नर्मदा घाटी विकास विभाग की 138.29 करोड़ रुपये लागत की अंबा रोडिया सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना का लोकार्पण भी करेंगे, जिससे 40 गांवों के 9,915 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री द्वारा जिन अन्य कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया जाएगा, उनमें धूलकोट से जूना बिलवा तक 7.70 किलोमीटर सड़क निर्माण (4.20 करोड़ रुपये), बिरोठी में आंगनवाड़ी भवन (28 लाख रुपये), मंडलेश्वर में 50 बिस्तर का सिविल अस्पताल भवन (8.94 करोड़ रुपये), खरगोन मेडिकल महाविद्यालय की चारदीवारी (3.78 करोड़ रुपये), तथा बरगोन-देवली से बेरूड़ मार्ग पर पुल निर्माण (2.98 करोड़ रुपये) शामिल हैं। कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर भव्या मित्तल ने स्थल, हेलीपैड और मंच की तैयारियों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बाइक शोरूम में चोरी, सीसीटीवी में तीन संदिग्ध कैद

माही की गूंज, बड़वानी।

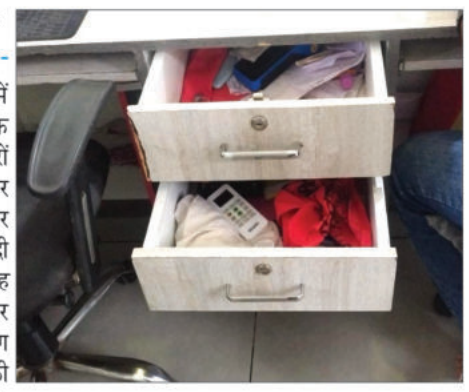

बड़वानी में टीवीएस बाइक शोरूम में चोरों ने शटर तोड़कर 12 से 15 हजार रुपये की नकदी चुरा ली। यह वारदात बुधवार सुबह लगभग साढ़े 4 बजे की बताई जा रही है।

शोरूम के कर्मचारी जब सुबह काम पर पहुंचे तो शटर टूटा हुआ मिला। उन्होंने तुरंत शोरूम मालिक अभिषेक फडणवीस को जानकारी दी। घटनास्थल पर लगे बंद कैमरे (सीसीटीवी) की रिकॉर्डिंग में तीन संदिग्ध व्यक्ति नजर आए हैं।

बंद कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच शुरू

चोरों ने अंजड़ रोड स्थित दो एमआरएफ टायर दुकानों में भी चोरी की कोशिश की थी। शहर कोतवाली पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और बंद कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच प्रारंभ कर दी है।

थाना प्रभारी दिनेश चौहान ने बताया कि रिकॉर्डिंग के आधार पर चोरों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

केएफडब्ल्यू प्रतिनिधिमंडल ने सेंधवा में सीवरेज परियोजना की प्रगति की समीक्षा की

माही की गूंज, बड़वानी।

मध्यप्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड, परियोजना क्रियान्वयन इकाई खरगोन के अंतर्गत सेंधवा नगर निकाय में संचालित केएफडब्ल्यू सहायता प्राप्त सीवरेज परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए 18 जून को जर्मन विकास बैंक केएफडब्ल्यू का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सेंधवा पहुँचा।

प्रतिनिधिमंडल में लूकास मेस, रायनर क्रूस, राहुल मनकोटिया तथा मोहो चतुर्वेदी शामिल थे। मध्यप्रदेश शहरी विकास कंपनी की ओर से सहायक परियोजना अधिकारी संजय पांडे, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. बनवारीलाल यादव, उपयंत्री गौरव ढाने एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता संस्था की ओर से दल प्रमुख अभिनव गोयल, विशेषज्ञ युवा कार्तिक, अनुज दीक्षित तथा पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. सीमा श्रीवास्तव और छाया खले उपस्थित रहीं। संविदाकार बटुक भाई रवि पटेल एवं उनकी टीम भी इस अवसर पर मौजूद रही।

एक दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना के सभी प्रमुख घटकों का स्थल निरीक्षण किया तथा कार्य की गुणवत्ता, प्रगति और क्रियान्वयन रणनीति की समीक्षा करते हुए कार्यों की सराहना की। प्रतिनिधियों ने सीवरेज कनेक्शन को लेकर नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की।

विशेष रूप से कल्पतरु संस्था द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक को देखा गया, जिसे प्रतिनिधियों ने प्रभावी बताया और उनके प्रयासों की प्रशंसा की। निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधियों ने कार्यों की गति एवं गुणवत्ता से संबंधित कई उपयोगी सुझाव दिए और समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया।

प्रतिनिधिमंडल ने सभी संबंधित अधिकारियों से आपसी समन्वय बनाकर कार्य को तत्परता से आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

दादाजी धूनीवाले मंदिर नवनिर्माण का भूमिपूजन 30 जून को

माही की गूंज, खंडवा।

खंडवा जिले के प्रसिद्ध दादाजी धूनीवाले मंदिर के नवनिर्माण का भूमिपूजन 30 जून को होगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संत समाज के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।

मंगलवार को कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर संयुक्त कलेक्टर अंशु जावला, नगर निगम आयुक्त प्रियंका राजावत, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, विद्युत कंपनी के सहायक यंत्री और मंदिर ट्रस्ट के तीन सदस्यों ने स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान स्थायी मूत्रालय निर्माण कार्य की समीक्षा की गई तथा अस्थायी मूत्रालयों को हटाने के निर्देश दिए गए। आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था, सजावट और अन्य सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कार्यक्रम की समय-सारणी पर विस्तार से चर्चा की।

इसी दौरान, नगर निगम आयुक्त प्रियंका राजावत ने आईटीआई के पीछे निर्मित विसर्जन कुंड का भी निरीक्षण किया। 50 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा यह कुंड मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार किया गया है। आयुक्त ने सुरक्षा की दृष्टि से कुंड के चारों ओर बाड़ लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मवेशियों या अन्य जानवरों को कोई खतरा न हो।

नेता प्रतिपक्ष बोले - बिहार चुनाव के लिए हो रही जातिगत जनगणना की चर्चा

माही की गूंज, खंडवा।

मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बुधवार को खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और इसके बाद बुरहानपुर के धूलकोट में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में भाग लिया। खंडवा में सिंघार ने मीडिया से चर्चा करते हुए जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ÷क्या बिहार में चुनाव या राहुल गांधी द्वारा मुद्दा उठाए जाने के कारण जातिगत जनगणना की बात हो रही है? भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो गई है।÷ उन्होंने 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना, परिसीमन और महिला आरक्षण पर स्पष्ट निर्देश देने की मांग की।

इस दौरान सिंघार ने खंडवा के एकमात्र रेलवे पुल का निरीक्षण किया। पुल की जर्जर स्थिति और बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हजारों नागरिक, स्कूल के बच्चे और अधिकारी रोज़ाना अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल से गुजरते हैं।

इस अवसर पर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मुन्ना राठौर भी मौजूद थे। राठौर ने कहा कि जिस तरह भोपाल में एक पुल को 90 डिग्री मोड़ दिया गया, वैसा ही हाल खंडवा की तीन पुलिया योजना का न हो जाए, जो वर्षों से अधूरी पड़ी है।

इस पर सिंघार ने कहा कि यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि जनता की ज़िंदगी और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस विषय में मुख्यमंत्री, आयुक्त और कलेक्टर से चर्चा कर पुल निर्माण कार्य को गति दी जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो वह विधानसभा में प्रश्न उठाकर इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाएंगे।

अमेरिका के पाकिस्तानी मोह मे फंसने की तार्किकता

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ़ भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई के औचित्य को समझाने के वास्ते पिछले दो हफ़्तों में 40 से ज़्यादा भारतीय राजनेताओं और पूर्व राजनयिकों से बने सात प्रतिनिधिमंडल 33 देशों में भेजे गए, लेकिन गत 14 जून को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित परेड में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख और अब फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया गया। इस बार की परेड में कुछ पुराना फौजी साजो-सामान 1991 के बाद पहली बार दिखा- 6,600 सैनिक, 28 अब्राम टैंक, 28 ब्रैडली लड़ाकू वाहन, 28 स्ट्राइकर वाहन, चार पैलाडिन सेल्फ-प्रोपेल्ड हॉवित्ज़र तोपें, आठ मार्चिंग बैंड, 24 घोड़े, दो खच्चर और एक कुत्ता - कुछ रॉकेट लॉन्चर और प्रिसिजन-गाइडेड मिसाइलें भी। इस रोज़ डोनॉल्ड ट्रंप का 79वां जन्मदिन भी था।

इस बीच, सांसदों के सभी सातों प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौट आए और उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। लंदन, पेरिस, रोम, कोपेनहेगन, बर्लिन और ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय की यात्रा पर गए भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने लौटने पर संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने इन सभी यूरोपीय शहरों में अपने वार्ताकारों को आतंकवाद के प्रति भारत की 'ज़ीरो टॉलरेंस' बारे बताया। प्रसाद ने कहा- 'हमने साफ कर दिया कि हम पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं। समस्या पाकिस्तान के जनरलों से है, जिनसे खुद वहां के लोग भी तंग आ चुके हैं।' लगता है प्रसाद खबरों को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। दो दिन पहले ही वाशिंगटन डीसी में, यूएस सेंट्रल कमांड के शक्तिशाली कमांडर जनरल माइकल ई कुरिल्ला ने यूएस सीनेट सशस्त्र सेवाएं समिति को बताया कि पाकिस्तान एक 'खास साझेदार' है, खासकर आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर।

कुरिल्ला ने आगे कहा, 'मुझे नहीं लगता कि यह कोई बाइनरी स्विच जैसा होना चाहिए कि यदि हम भारत के साथ संबंध रखें, तब हमें पाकिस्तान के साथ (संबंध) नहीं रखने चाहिए।' इससे कुछ दिन पहले, कुरिल्ला के बॉस, डोनॉल्ड ट्रम्प ने भी घोषणा की थी, 'पाकिस्तान के पास बहुत मजबूत नेतृत्व है। कुछ लोगों को यह नागवार लगता है जब मैं ऐसा कहता हूं, लेकिन हुआ यही है, और उन्होंने उस युद्ध को रोक दिया। मुझे उन पर बहुत गर्व है। क्या मुझे श्रेय मिल रहा है? नहीं। वे मुझे किसी भी चीज़ का श्रेय नहीं दे रहे।'

तब भारत और अमेरिका के बीच प्रसिद्ध 'रणनीतिक साझेदारी' का क्या बना? इसके अलावा, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हमें सख्त नापसंद 'हाइफ़नेशन' (दोनों को बराबर पलड़े में तोलना) फिर से बन गया है? बड़ा सवाल, बेशक, यह कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अभी भी ऐसे मुल्क के मोहपाश में क्यों फंसा है, जिसकी अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है (आईएमएफ से 25 ऋण ले रखे हैं), जो कहने भर का लोकतंत्र है और भारत में आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड बना हुआ है, जिसमें नवीनतम कांड पहलगाम में हुआ दुर्दांत हमला है। निश्चित रूप से, काली दाल में फिर कड़छी चल रही है। कम-से-कम 2008 के बाद से, जब भारत और अमेरिका ने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे,जहां अमेरिकी भारत के साथ साझेदारी के लिए उत्सुक रहे वहीं ऐसे ही भारतीय भी। यह सिर्फ इस बारे नहीं था कि भारत कितने बोइंग विमान खरीदेगा, हालांकि इससे रिश्तों में मदद मिल सकती थी। अमेरिका ने व्यापारिक आदान-प्रदान पर टिकी साझेदारी से परे वास्तविक संबंध की कीमत को पहचाना, जिसमें भारत को चीन के प्रति-संतुलन के रूप में देखा जाने लगा।

लेकिन ट्रम्प ने आपसी व्यापार में लेन-देन में बराबरी रखने की अपनी प्रवृत्ति के साथ दुनिया में उलटफेर कर दिया। पाकिस्तान को एक नयी राह की तरह देखा जाने लगा है। हिलेरी क्लिंटन ने 2012 में पाकिस्तान को लेकर दुविधा को बहुत भावुकता से व्यक्त किया था 'बात यह नहीं कि आपने पिछवाड़े में कितने सांप पाल रखे हैं, और क्या वे आपको नहीं डंस सकते'। एक बार फिर मामला है कि आप अमेरिकियों को एक-दो सांप ऐसे सौंप दें कि वे आपकी सपेरागिरी के कायल हो जाएं।

यहां तीन कारण हो सकते हैं कि क्यों पश्चिमी देश पाकिस्तान के मोहपाश में फंसने को तैयार हैं-पहला, आतंकियों पर पाकिस्तान का निरंतर प्रभाव उसे एक कीमती मित्र बनाता है। हाल ही में, पाकिस्तान ने मोहम्मद शरीफुल्लाह 'जफ़र' सहित इस्लामिक स्टेट के पांच लड़ाके अमेरिकियों को सौंपे, जो 2021 में काबुल हवाई अड्डे के पास बम हमले में शामिल थे, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। तथ्य तो यह कि भले ही 'जफ़र' इस काबुल हमले का मास्टरमाइंड रहा हो, लेकिन वह आईएस के शीर्ष नेतृत्व में नहीं था। उसे सौंपकर मुनीर अपने लिए समय और प्रभाव खरीद रहे हैं- पाक की अमेरिका को लेकर रणनीति का अभिन्न अंग, जो दशकों कारगर रहा।

कुरिल्ला द्वारा पाकिस्तान की प्रशंसा के तुरंत बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दो प्रमुख समितियों में पाकिस्तान को अहम ओहदों पर को नामित किया गया- तालिबान पर प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता और आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष। जब अमेरिका को अहसास हो गया है कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान की उपयोगिता भले कामों में बरतने की अपेक्षा नुकसान पहुंचाने वालों से निबटने में कहीं अधिक है,तो क्यों न राक्षस को कुछ-कुछ निवाला डालते रहें ताकि वह काबू में रहे? दूसरा, जब कोई ट्रंप को ना कह दे या बात काटे, तो यह उनके बेहद अहंकारी स्वभाव को रास नहीं आता। इसलिए जब उन्होंने और उनके सहयोगियों ने 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के लिए 'मध्यस्थता' करने की घोषणा की, तब भारत ने यह बात नकार दी ट्रंप यह बात 12 बार और दोहरा चुके हैं)। हकीकत यह कि भारतीय वायु सेना ने 10 मई को 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला करके करारा संदेश दिया, जिसने पाकिस्तानियों और अमेरिकियों, दोनों में,'ईश्वरीय भय' पैदा कर दिया, और संघर्ष जल्द खत्म हो गया। ट्रंप जो भी कहें, उसे नकारने की जहमत क्यों उठाएं?

ज्योति मल्होत्रा

तीसरा, पाकिस्तान खुद को पीड़ित दिखाने में माहिर है, यह कोई छोटी विडंबना नहीं। भारत को घिनौनी रंगत देने वाले अभियान को आगे बढ़ाकर कि 'भारत सिंधु नदी के पानी को रोक 23 करोड़ लोगों को प्यासा मारना चाहता है'), वह वैश्विक सहानुभूति पाने की कोशिश में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाशिंगटन व लंदन में बिलावल भुट्टो की मुहिम का उद्देश्य यही था। आतंकी हमलों में पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान की भूमिका बारे सवालों को इस प्रश्न से दरकिनार कर दिया जाता है कि 'सबूत कहां है?' पाकिस्तान आतंकवाद के साथ अपने अनुभवों की तुलना मुंबई आतंकी हमले में अजमल कसाब जैसा ठोस सबूत पाने से करना चाहता है, जिसमें लगभग 170 लोग मारे गए थे।

अमेरिका की सहानुभूति दिख रही है। जनरल कुरिल्ला ने कहा कि 2024 में पाकिस्तान को करीब 1,000 आतंकी हमले सहने पड़े, जिसमें 700 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 2,500 घायल हुए। सवाल है कि अब आगे क्या। जनरल मुनीर ने अमेरिकियों को शीशे में उतार लिया है, लिहाजा अमेरिकी सेना की परेड में उनकी उपस्थिति, उन्हें कुछ मांगें और करने का मौका देगी। पाक-अमेरिका व्यापार में शून्य-टैरिफ का अनुरोध किया जाएगा; इससे भी महत्वपूर्ण है कि यह सुझाव दिया जाएगा कि अमेरिका भारत पर सिंधु जल संधि बहाल करने और वार्ता फिर से शुरू करने को दबाव डाले। ग्रीष्म ऋतु आगे लंबी और कठिन होने वाली है। हो सकता है भारत के पास कुछ पत्ते हों, लेकिन उसे यह सीखना होगा कि उन्हें सीने से लगाकर न रखे। पाकिस्तान की बेईमानी बारे अपना आकलन साझा करें, लेकिन इस बात पर घमंड न करे कि वह बड़ा और बेहतर दक्षिण एशियाई राष्ट्र है।

बेहतर होगा कि अपने अंदर झांकें और अपने चाणक्य या फिर सन त्जु को फिर पढ़ें। जिनके मुताबिक 'अपने दोस्तों को हमेशा करीब रखना अच्छा विचार है, लेकिन दुश्मनों को और भी नज़दीक रखें।'

महाकाल के दर्शन के लिए आसान नहीं है मंदिर तक पहुंचने की राह

माही की गूंज, उज्जैन।

देश-विदेश से भगवान महाकाल के दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए मंदिर की राह आसान नहीं है। श्रद्धालुओं को संकरे रास्तों से होते हुए मंदिर पहुंचना पड़ रहा है। मार्ग में नालियां खुली होने से कई दर्शनार्थी हादसे का शिकार हो रहे हैं। मंदिर व जिला प्रशासन का भक्तों को होने वाली इस परेशानी की ओर ध्यान नहीं है। समय रहते अव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया, तो श्रावण-भाद्रपद मास में परेशानी बढ़ सकती है।

महाकाल मंदिर में नवनिर्माण के चलते प्रशासन ने शहनाई द्वार के सामने वाली मुख्य सड़क पर आवागमन प्रतिबंधित कर रखा है। इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं को मंदिर के 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर गेट तथा माधव सेवा न्यास व महाराजवाड़ा पार्किंग तक आने जाने के लिए सामने की ओर एक संकरी गली के रूप में वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया गया है।

परिवर्तित मार्ग बना भक्तों के लिए परेशानी

यही परिवर्तित मार्ग भक्तों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। इस छोटे से मार्ग पर दोनों ओर अतिक्रमण पसरा है। मध्य में आने जाने के लिए जो स्थान बचा है, उसमें बड़ी-बड़ी नालियां खुली पड़ी है, जिसके कारण दिनभर में कई हादसे होते हैं।

सुबह व शाम के वक्त भीड़ अधिक रहती है उस समय तो भक्त भगवान महाकाल के भरोसे ही यह सड़क पार कर पाते हैं। साफ सफाई नहीं होने से नालियों से दुर्गंध उठती रहती है। आसपास के दुकानदार कूड़ा कचरा भी खुले में ही डाल देते हैं।

अफसर झांकने तक नहीं आते क्या है परेशानी

माधव सेवा न्यास की पार्किंग से यादव समाज की धर्मशाला, गोपू बालेश्वर महादेव मंदिर के सामने से व महल वाली गली तक का रास्ता परिवर्तित मार्ग है। इस मार्ग पर फूल प्रसाद, पूजन सामग्री, रूद्राक्ष, फोटो, मूर्तियां यहां तक कि जूता चप्पल बेचने वाले दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है।

इसके अलावा भक्तों को माला, सिक्के, कलावा बेचने वाले फेरी लगाते रहते हैं। तिलक लगाने वाले लोगों की मौजूदगी भी यहां देखी जा सकती है। इन सब समस्याओं से जूझते तथा व्यवस्था को कोसते हुए भक्त मंदिर पहुंचते हैं। भक्तों को होने वाली इन तमाम परेशानी के बावजूद मंदिर व जिला प्रशासन का कोई अधिकारी यहां झांकने तक नहीं आता है।

रातभर खुला रहता है मार्केट

महाकाल मंदिर के सामने कोट मोहल्ला तक दोनों ओर होटल व रेस्टोरेंट की श्रृंखला है। कुछ लोगों ने दूध, मिठाई की दुकानें लगा रखी है। सुबह से शाम तक यहां यात्रियों की भीड़ रहती है। आटो व ई रिक्शा चालकों ने यहां अवैध पार्किंग लगा रखी है। शाम होते ही चाय, नाश्ता, पराठे, पोहे आदि के ठेले लग जाते हैं, सारी रात यह मार्केट खुला रहता है। व्यवस्था, सुरक्षा दोनों ही दृष्टि से यह उचित नहीं है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं देते हैं।

राजा के नगर भ्रमण के लिए तैयार हो रहा मार्ग

ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 11 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत होगी। देशभर से हजारों भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आएंगे। श्रावण-भाद्रपद मास में भगवान महाकाल की सवारी भी निकलेगी।

अवंतिकानाथ चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। इसको लेकर जोरशोर से तैयारी जारी है। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा शहनाई गेट से मुख्य मार्ग तक सीमेंट कांक्रीट का रोड बनाया जा रहा है। सावन-भादौ मास में इसी मार्ग से भगवान महाकाल की सवारी नगर भ्रमण के लिए निकलेगी।

पेड़ों की कटाई के पूर्व 300 पौधे रोपे जाए- कलेक्टर

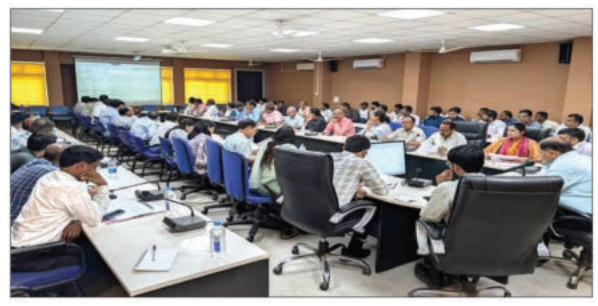

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर सभा कक्ष में किया गया। इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर सिंह, अनुविभागीय अधिकारी अर्थ जैन, अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री प्रियांशी भंवर, अनुविभागीय अधिकारी तपीस पांडे, डिप्टी कलेक्टर जीपी अग्रवाल, सुश्री निधि मिश्रा सहित संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित थे। इस दौरान 50 दिवस से अधिक शिकायतों की समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा किखंडवा बड़ौदा मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान लगभग 30 पेड़ों को काटने पर ही 5-5 फिट रोड चौड़ा हो पाएगा। इन पेड़ों की कटाई के पूर्व कॉलेज परिसर की ब्राउण्डीवॉल के समीप 300 पौधे रोपे जाए, उसके बाद ही प्रमुख मार्ग पर पेड़ कटाई करना प्रारंभ करें। इस दौरान उन्होंने धरती आबा के तहत आयोजित शिविर मे संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अधिक से अधिक ग्रामीण जनों को जन कल्याण से संबंधित योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि, अनुकंपा से संबंधित आवेदनों पत्र का पात्रता अनुसार निराकरण करें अन्यथा अपात्र होने पर संबंधित शिकायत को फोर्स क्लोज करना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जमीन विवाद या आपसी बंटवारे के प्रकरणो को तुरंत निराकरण करें। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि दिनांक 21 जून को योग दिवस का आयोजन जिला स्तर पर किया जाएगा सभी अधिकारी दिए गए दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होने ई ऑफिस की प्रक्रिया के माध्यम से ही फाइल के निराकरण करने के निर्देश दिए।

जेल में बनेंगे खाने में उपयोग होने वाले पोष्टिक मसाले

माही की गूंज, उज्जैन।

पहली बार, उज्जैन सेंट्रल जेल के अधिकारी भैरवगढ़ जेल परिसर में एक मसाला निर्माण और पैकेजिंग यूनिट स्थापित करने जा रहे हैं। जहाँ तैयार मसाले जिले की अन्य उपजेलों में भी भेजे जाएँगे। इसके लिए जेल विभाग अपने कैदियों को विशेष प्रशिक्षण दिलवाएगा, ताकि वे रिहा होने के बाद भी आजीविका कमाने के लिए तैयार हो सके।

जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया कि, मसाला यूनिट स्थापित करने के लिए जेल में एक सेटअप तैयार किया गया है। यहाँ जल्द ही मसाला पीसने के लिए आवश्यक मशीनें स्थापित की जाएगी। इसके लिए कैदियों को मसालों को पीसने, अलग करने, सुखाने और पैकिंग के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक विशेष टीम तैनात की जाएगी। खास बात यह है कि मसाला यूनिट में काम करके कैदियों को न केवल अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए मजदूरी मिलेगी, बल्कि उन्हें खाना पकाने के लिए शुद्ध मसाले भी मिलेंगे। बता दें कि पूरे प्रदेश में पहली बार जिला जेल उज्जैन में मसाला यूनिट शुरू होने जा रही हैं। इसका उद्देश्य विचाराधीन और दोषी कैदियों को खाद्य मसाला निर्माण और पैकेजिंग उद्योग का प्रशिक्षण देना है, ताकि जेल से रिहा होने के बाद वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।

उपजेलों में यहीं का मसाला होगा उपयोग

उल्लेखनीय है कि, यूनिट में मसाला तैयार करने के लिए जेल अधिकारी बाजार से कच्चा माल खरीदेंगे और मसालों को चुनने, अलग करने, साफ करने, सुखाने, पीसने और पैकेजिंग के काम में प्रशिक्षण प्राप्त कैदियों को लगाएँगे। इसके बाद तैयार मसाले को शुरुआती चरण में भैरवगढ़ जेल सहित जिले की अन्य उप जेलों में उपयोग किया जाएगा। उत्पादन बढ़ने के साथ इसे बाहर भी विक्रय किया जाएगा। जाहिर है कि उज्जैन जेल के अधिकारियों ने वास्तव में एक अत्याधुनिक पैकेजिंग यूनिट स्थापित करने के अलावा सरकारी कार्यालयों, मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले स्कूलों, साथ ही निजी फर्मों और बाजारों में रसोई और कैंटीनों में मसाले बेचने के लिए एक विपणन टीम को काम पर रखने की योजना बनाई है जो समय के साथ साथ नई ऊँचाईयों को छुएगी।

चीता शावक मां और भाई-बहनों से बिछड़ा

श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए चीतों का कुनबा अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है। चीतों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं।

हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो हर किसी को भावुक कर रहा है। यह वीडियो मई महीने के आखिरी सप्ताह का बताया जा रहा है। पार्क में घूमने आए कुछ पर्यटकों को अचानक एक चीता शावक नजर आया जो अलग तरह की आवाज निकाल रहा था।

अलग तरह की आवाज निकालता दिखा चीता

पर्यटकों ने देखा कि यह शावक बार-बार एक विशेष प्रकार की हल्की चहचहाहट जैसी आवाज निकाल रहा था। बताया जा रहा है कि यह शावक अपनी मां और भाई-बहनों से बिछड़ गया था और उन्हें ढूंढने के लिए लगातार पुकार लगा रहा था। इस भावुक दृश्य को पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कूनो पार्क में निजी सफारी संचालक आदर्श गुप्ता ने फोन पर पुष्टि की कि यह वीडियो पिछले महीने लिया गया था और अब तेजी से वायरल हो रहा है।

शावक अपनी मां और भाई-बहनों से बिछड़ गया था

प्रोजेक्ट चीता के डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि चीते इस तरह की आवाजें अपने साथियों को बुलाने के लिए निकालते हैं। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, शावक जब बिछड़ते हैं या खतरा महसूस करते हैं तो ऐसी आवाजें निकालते हैं।

विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनीष कुमार मिश्रा महोदय के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत गिराला एवं नानपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर के दौरान जय पाटीदार द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता योजना की जानकारी देते हुए बताया कि, ऐसा कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति -जनजाति का सदस्य हो, बालक या महिला हो, औद्योगिक कर्मकार हो या जिसकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये दो लाख से कम हो ऐसा व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकारी होता है, योजना अंतर्गत न्याय शुल्क एवं अधिवक्ता शुल्क व प्रतिलिपि शुल्क की व्यवस्था प्राधिकरण के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है तथा लाभांवित व्यक्ति को कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगता। इसके साथ ही श्री पाटीदार द्वारा नालसा (आदिवासियों के अधिकारों संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीप सिंह मुजाल्दा द्वारा नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विधिक सेवाएं) योजना 2015 की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मूल उद्देश्य सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को गरीबी उन्मूलन योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तहसील स्तर पर कानूनी सहायता प्रदान करना है। साथ ही उपस्थित ग्रामीणों को लोकोपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत, मध्यस्थता योजना, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना आदि के बारे में भी बताया गया।शिविर में जय पाटीदार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दिलीप सिंह मुजाल्दा जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा सहभागिता की गई।

पुलिस ने चोरी के चार प्रकरणों का किया खुलासा

माही की गूंज, नानपुर।

जिला अलीराजपुर के कस्बा नानपुर में हाल ही में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर राजेश व्यास के निर्देशन में थाना नानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए वाहन चोरी के 4 प्रकरणों का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया गया है।

दिनांक 23 मई की रात्रि में कस्बा नानपुर से एक ही रात में तीन अलग-अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं घटित हुई थीं, जिस पर से थाना नानपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। एक ही रात में तीन घटनाओं की संवेदनशीलता एवं क्रमबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर द्वारा अज्ञात अपराधियों की धरपकड हेतु थाना प्रभारी नानपुर के नेतृत्व मे टीम गठित कर शीघ्र पतासाजी करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम टांडा पीपलबात डाबरिया फलिया, जिला धार में दबिश दी गई, जहां से वाहन चोरी की घटनाओं में संलिप्त तीन आरोपियों नानकिया पिता कालू भील, चीतू पिता करम सिंह भील एवं एक नाबालिग को विधिवत गिरफतार किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा चोरी की गई मोटरसाइकिलों के संबंध में अपराध स्वीकार किया गया, जिनके कब्जे से कुल 4 मोटरसाइकिलें, जिनमें तीन मोटर सायकिल नानपुर कस्बें से एवं 01 मोटर सायकिल गुजरात राज्य से चुराई गई है एवं घटना में प्रयुक्त एक अन्य मोटरसाइकिल को विधिवत जप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर राजेश व्यास ने बताया कि नानपुर कस्बें हुई वाहन चोरी के प्रकरण में तीव्र कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस द्वारा न केवल आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया, बल्कि चोरी गई सम्पत्ति की भी बरामदगी सुनिश्चित की गई है, जो कि नानपुर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी नानपुर उनि मुकेश कनसिया एवं अधीनस्थ टीम के सदस्यों सहायक उप निरीक्षक नर्सिंग सेंचा, प्रधान आरक्षक 285 मनोज माइकल, प्रधान आरक्षक 154 संजय मंडलोई, आरक्षक 394 कांतिलाल एवं आरक्षक 197 धन सिंह की भूमिका रही है।

सिविल सर्जन को हटाया, आतिशबाजी कर कर्मचारियों ने मनाई खुशी

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले में स्थित संभाग का सबसे बड़े सरकारी अस्पताल चरक भवन खुद बीमार है। अफसरों की फौज के बावजूद अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार होने पर एनडीटीवी ने 18 दिन पहले सच उजागर किया था। इसके बाद डॉक्टर्स और सिविल सर्जन में मतभेद हो गए थे, जिसकी शिकायत सीएम मोहन यादव तक पहुंची थी। नतीजतन शासन ने सोमवार को सिविल सर्जन को हटा दिया है।

सिविल सर्जन डॉ अजय दिवाकर को पद से हटाया गया

बता दें कि, कोयला फाटक के नजदीक संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल चरक भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इस छह मंजिला अस्पताल में बड़ी संख्या में डॉक्टर, कर्मचारी और अधिकारी तैनात हैं। इसके बावजूद यहां फैली अव्यवस्थाओं के कारण अस्पताल खुद बीमार नजर आता है। इसी हालात को देखते हुए 29 मई को एनडीटीवी ने अस्पताल परिसर से लेकर सभी मंजिल पर बने हर वार्ड में फैली अव्यवस्थाओं को उजागर किया था। जिसके बाद अव्यवस्थाओं को लेकर अन्य डॉ विक्रम रघुवंशी और स्टाफ का सिविल सर्जन डॉ अजय दिवाकर से विवाद हुआ था। वहीं शिकायत के बाद शासन ने डॉ दिवाकर को ट्रांसफर कर डिंडोरी भेज दिया और उनकी जगह सीएमएचओ अशोक कुमार पटेल को सिविल सर्जन बना दिया।

अस्पताल में यह हैं अव्यवस्था

जिला अस्पताल के बेसमेंट में पार्किंग में बाहरी लोगों की गाड़ियां पार्क होंने के साथ इमरजेंसी और शिशु वार्ड के पास सिवरेज का पानी सड़क पर बहने के कारण चारों ओर फैल रही है। सिवरेज के कारण कई माह से बदबू फैल रही है। मरीजों की सुविधा के लिए लगी 10 में से 6 लिफ्ट कई महीनों से बंद पड़ी है। शौचालयों में नल की टोटी, शीट और टाइल्स टूटी पड़ी है और प्रसूताओं को घर से पंखा लेकर आना पड़ रहा है।

सिविल सर्जन को हटाने पर आतिशबाजी

सिविल सर्जन डॉ दिवाकर का ट्रांसफर करने पर कर्मचारियों ने जमकर ढोल बजाकर नए सिविल सर्जन डॉ पटेल का स्वागत किया और फटाके फोड़े। वहीं डॉ पटेल ने कहा कि एनडीटीवी की खबर से अव्यवस्था की जानकारी उन्हें भी लगी थी। जल्द ही सभी व्यवस्था सुधार ली जाएगी।

अच्छी शिक्षा राजनीति का शिकार, विकासखण्ड के ज्यादातर संकूल प्रभारी प्राचार्यो के भरोसे

नियमित प्राचार्य मालवीय के स्थानांतरण के आदेश बने चर्चा का विषय

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

शिक्षा व्यवस्था का ढर्रा किस कदर बिगड़ा हुआ है या गंदी राजनीति के जरिये बिगाड़ा जा रहा है। इसका नमूना एक बार फिर पेटलावद संकुल में देखने को मिला जहाँ ज्यादातर संकुल प्राचार्य पद पर प्रभारी प्राचार्य ही व्यवस्था सम्भाल रहे हैं। सरकार के पास बड़ी संस्थाओं को संचालित करने के लिए नियमित प्राचार्य तक नही है और जो गिने चुने नियमित प्राचार्य है भी तो वो या तो राजनीतिक प्रेरित है या राजनीति का शिकार हैं । वर्तमान में स्थांतरण नीति लागू है और कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण की सूची सीधे भोपाल से जारी हो रही है। वही जिनके स्थानांतरण नही हो पा रहे उनको येन केन प्रकारेण स्थानीय स्तर पर ही नियम विरुद्ध इधर-उधर कर के अच्छी चलती व्यवस्था को बैसाखी मतलब प्रभारियों के भरोसे किया जा रहा है।

बरवेट संकुल प्राचार्य मालवीय का स्थानांतरण चर्चा में

अपनी तेज तर्रार छवि ओर नियम के पक्के जाने, जाने वाले पेटलावद विकास खण्ड के बरवेट संकुल नियमित प्राचार्य मोतीराम मालवीय का अचानक हुआ स्थांतरण चर्चा का विषय बन गया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित परीक्षा से पास होकर भोपाल से सीधे प्राचार्य पद पर नियुक्त होकर लगभग डेढ़ वर्ष से बरवेट संकुल क्षेत्र के प्राचार्य पद की जिम्मेदारी सम्भाल रहे है। उनके पदस्थ होने के बाद बरवेट संकुल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूल समय से संचालित होने लगे थे। स्कूली शिक्षकों को समय पर आना और जाना उनके द्वारा निश्चित किया गया। संकुल क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े नियम और उनका सख्ती से पालन उनके लिए समस्या बना हुआ था। वही उनकी सख्ती के चलते कई शिक्षक नाराज होकर शिकायत कर उनके स्थानांतरण की धमकी तक देने से नही चूकते। वर्तमान में स्थानांतरण सरकार कर रही है लेकिन प्राचार्य मोतीराम मालवीय का स्थानन्तरण कही होता नही दिखा तो स्थानीय स्तर पर जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विभाग की कलेक्टर द्वारा एक आदेश 17 जून 2025 को जारी किया गया। जिंसमे जिले के तीन प्राचार्या का स्थानन्तरण किया गया। स्थानन्तरण में बरवेट प्राचार्य मालवीय का नाम भी शामिल हैं जिनको थांदला ब्लॉक के बलवासा स्कूल के लिए स्थान्तरित कर दिया गया। पूरा आदेश गोलमाल ओर राजनीति से प्रेरित साफ दिखाई दे रहा है जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है।

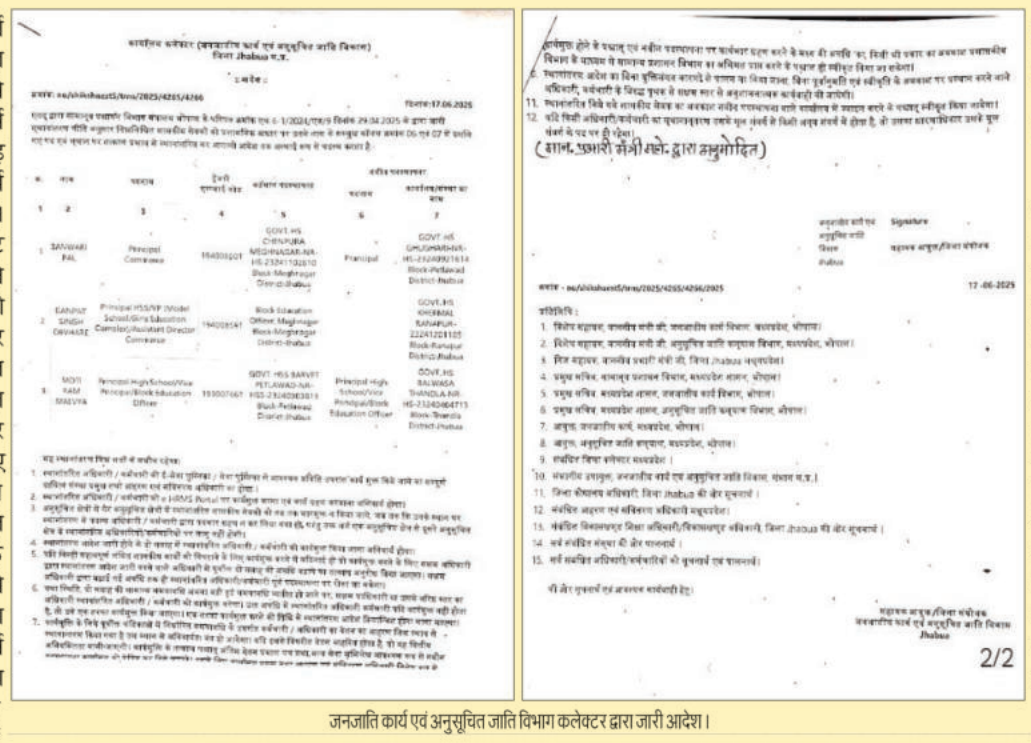

जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विभाग कलेक्टर द्वारा जारी आदेश।

राजनीतिक दबाव साफ, भोपाल से होना था स्थानन्तरण

आदेश को देखा जाए तो साफ पता चलता है कि, स्थानीय अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्थानन्तरण के आदेश जारी किए हैं। प्राचार्य मालवीय जोकि, भोपाल आयुक्त के आदेशानुसार पदस्थ हुए थे उनका स्थानन्तरण के अधिकार भी आयुक्त भोपाल के माध्यम से होना था। नियम के अनुसार 60 वर्ष से अधिक हों जाने पर अधिकारी, कर्मचारी को स्वेच्छिक स्थानन्तरण के अधिकार होते है। प्राचार्य मालवीय भी 60 से अधिक आयु के होने से उनके स्थानन्तरण के लिए अलग नियम लागू होने थे।

इस विषय मे जब जानकारी निकाली गई तो पता चला कि, स्थानीय अधिकारियों को केवल स्थानन्तरण के लिए अनुमोदन के अधिकार है ऐसे में सीधे-सीधे स्थानन्तरण होना कही न कही गंदी राजनीति और प्रभारी प्राचार्य बनने के लिए मची होड़ ओर लेन-देन की चर्चा पर मोहर लगाता दिख रहा है।

प्रभारी मंत्री से अनुमोदित लिखा हाथ से

वर्तमान में प्रभारी मंत्री जिले के दौरे पर लंबे समय से नही आये न कोई बैठक हुई। वही आदेश पर प्रभारी मंत्री की सहमति में कई हस्ताक्षर तक नही है पूरा आदेश कम्प्यूटर पर टाइप किय्या हुआ है। जिस पर अलग से हाथ से लिखा गया है प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित ,आखिर ऐसा क्यो किया गया है...? ये भी चर्चा का विषय है। कक्षा 10 वी ओर 12 वी के परिणाम की बात सामने आ रही है। बरवेट संकुल में 10 वी का परिणाम 60 प्रतिशत से अधिक तो 12वी का मात्र 31 प्रतिशत के लगभग रहा था जो अन्दर खाने से स्थानन्तरण का कारण बताया जा रहा है। जबकी विकास खण्ड की ओर भी ऐसी संस्थाएं है जिनका परिणाम इससे भी कम रहा लेकिन वहां के प्राचार्य को हटाया नही गया। खेर अधिकारीयो की आदेश के लिए जो भी मजबूरी रही हो इस प्रकार से जारी आदेशो से अच्छी शिक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारीयो का मनोबल टूटता है। साथ ही कामचोर ओर भ्रष्ट कर्मचारियों का उत्साह बढ़ता है। जो देश के भविष्य की तैयार होने वाली नींव को कमजोर करते हैं।

पति ने शंका पर की पत्नी की हत्या

माही की गूंज, काकनवानी। नरेश पंचाल

शनिवार दोपहर 1 बजे चंपाबाई अपने बच्चों के साथ घर में बैठी थी। तभी अचानक उसका पति घर में आया और लाठी से चंपा बाई को मारना पीटना शुरू किया और इस कदर मारा की उसे पेट में गहरी चोट लगने से मौत हो गई।

घटना इस प्रकार हुई कि, मृतिका के पति पर कर्ज था और वह गुजरात सूरत काम करने के लिए गया हुआ था। मृतिका चंपाबाई अपने बच्चे जैन्तु 14 वर्ष के साथ अपने घर पर ही रहती थी। 14 जून शनिवार को ग्राम पांच पिपल का एक व्यक्ति उसके घर आया जिसने मृतक के पति को उधार पैसे दे रखे थे जो पैसे लेने के लिए आया हुआ था। पैसे नहीं मिलने पर वापस लौटा और इसी समय मृतक चंपा बाई का पति सूरत से वापस आया और उस व्यक्ति को घर से जाते हुए देख लिया। जिस पर उसे अपनी पत्नी से अवैध संबंध की शंका हुई और उसने घर में आते ही अपनी पत्नी को ले से पीटना शुरू किया और उसके पेट में जमकर लाठी लगी जिससे चम्पा बाई ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतिका चंपाबाई पति बादरा उम्र 30 वर्ष निवासी धारा फ़लिया काकनवानी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 116/25 धारा 103 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया।

गूंज असर, हरकत में विभाग: तोड़े गए जर्जर भवनों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था में जुटा विभाग

माही की गूंज, बरवेट। जगदीश प्रजापत

तोड़े गए जर्जर भवन नही बन पाने के कारण नये सत्र में बच्चों और शिक्षकों को होने वाली समस्या को लेकर गूंज के पिछले अंक में खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर छपने के बाद शिक्षा विभाग तुरंत हरकत में आया और स्कूली बच्चो को बैठने के लिए भवनों की व्यवस्था को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की। हालांकि नवीन भवनों का निर्माण कब होगा इसकी कोई जानकारी फिलहाल नही है। ज्ञात रहे कि, पिछले सत्र में पेटलावद विकास खंड के अंतर्गत कुल 46 प्राथमिक विद्यालय एवं बरवैट संकुल के अंतर्गत पांच प्राथमिक विद्यालय के भवन जर्जर होने पर गत वर्ष गिरा दिए गए थे। नए भवन नही बनने पर विद्यालय का संचालन कहा होगा...? इसको लेकर पेटलावद बीआरसी रेखा गिरी, सीएससी रामेश्वर पाटीदार ने संकुल के पांचों गाव के प्राथमिक विद्यालय पहुचकर अस्थायी व्यवस्था की है।

प्राथमिक विद्यालय पिपलीपाड़ा में वैकल्पिक क्लास की व्यवस्था करती बीआरसी रेखा गिरी।

जब तक भवन की मरम्मत या पुनर्निर्माण का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक छात्रों के लिए अस्थायी कक्षाओं की व्यवस्था की है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो।

दूसरे विभाग के भवनों में परिवर्तन किया गया

बरवेट संकुल के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय गोठानिया को सामुदायिक भवन, प्राथमिक विद्यालय महुडीपाड़ा खुर्द को आंगनवाड़ी भवन, प्राथमिक विद्यालय पिपलीपाडा को आंगनवाड़ी भवन में, प्राथमिक विद्यालय गरवाड़ी को आंगनवाड़ी भवन में, प्राथमिक विद्यालय कालीघाटी को आंगनवाड़ी भवन में परिवर्तन किया गया है। अब छात्रों की क्लास अन्य विभाग के भवन में लगेगी ये वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती हैं। जिससे विभाग और पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा प्रभावित इस सत्र में होना तय है। विभाग को चाहिए कि समय रहते नये भवन स्वीकृत करवा कर निर्माण करवाये ताकि इस प्रकार की परेशानी बच्चों को नही हो।

चारण कोटड़ा से लाबरिया तक माही डैम मार्ग हुआ बदहाल

तीर्थयात्रियों सहित ग्रामीणों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना

माही की गूंज, रायपुरिया।

झाबुआ और धार जिले को जोड़ने वाला माही डैम मार्ग पूर्णतः जर्जर हो चुका है। झाबुआ जिले कि सीमा पर स्थित चारण कोटड़ा गांव से प्रारंभ होकर धार जिले के लाबरिया तक जाने वाले लगभग 4 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। इस मार्ग से गुजरने के लिए राहगीरों और वाहन चालको को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। ओर यह मार्ग अभी से आवाजाही में मुश्किल खड़ी करने लगा है। इस मार्ग की बरसात के मौसम में स्थिती और भी बिगड़ जाती हैं। वर्तमान स्थिति में उक्त मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। ओर डामर ओर गिट्टी पूरी तरह उखड़ चुकी हैं। यह मार्ग माही डैम से होकर निकलता है। जिसका निर्माण जल संसाधन विभाग ने कई वर्षों पहले करवाया था। लेकिन उसके बाद आज तक इस मार्ग की मरम्मत नहीं करवाई गई।

तीर्थस्थानों के लिए मुख्य मार्ग

इस मार्ग की खराब स्थिति का सबसे ज्यादा असर विश्वमंगल हनुमान धाम तारखेड़ी,उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, कोटेश्वर तीर्थ पर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ रहा है। श्री विश्वमंगल धाम तारखेड़ी, झाबुआ जिले का प्रमुख तीर्थ स्थल है। जहां प्रति मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ दर्शन हेतु पहुंचते हैं। इसके साथ ही इस मार्ग पर धार जिले के बदनावर और आसपास के कई गांव के लोग दर्शन करने आते है। इसी के साथ पास ही माही नदी किनारे स्थित श्रृंगेश्वर धाम पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध धाम है। जहां सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपयो की योजना पर काम चल रहा है।

चारण कोटड़ा निवासीयों ने बताया कि, प्रतिदिन सैकड़ो दोपहिया -चारपहिया वाहन इस मार्ग से गुजरते है। सड़क की जर्जर हालत के चलते दुर्घटना की संभावना बनी रहती हैं। वहीं किसानों का कहना है कि, यही सड़क बन जाती है तो करीबन 40 गांवों के लोगों का सीधा संपर्क क्षेत्र की बड़ी कृषि मंडी बदनावर से हो जाएगा। जिससे किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बदनावर क्षेत्र की बड़ी मंडियों में से एक है।

पैदल विहार करने वाले संतों को हो रही परेशानी

जैन समाज की अमूल्य धरोहर हैं साधु संतों को उग्र विहार कर झाबुआ जिले से धार जिले के लिए यही कम किलोमीटर पर पहुंचने वाला सुगम मार्ग है लेकिन यह मार्ग जर्जर होने से साधु संतों को भी इस कंकरिया पथरीले जर्जर मार्ग से गुजरने में बहुत तकलीफ होती है। इस ओर ध्यान आकर्षित कर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहिए। इस हेतु पूर्व में भी मध्यप्रदेश महिला बाल विकास विभाग कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया को अवगत करवाया गया था। लेकिन आज तक इस ओर कोई किसी ने भी ध्यान केंद्रित नहीं किया गया।

इसके साथ ही धार जिले के सरदारपुर विधायक को इस हेतु अवगत करवाने पर उनका कुछ माह पूर्व कहना था कि, यह सड़क मंजूर करवाने के लिए अंतरजिला योजनांतर्गत फाइल भेज दी गई है। जनता को जिस पर आस है वह आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे पा रहे।

किसान तीन माह से हो रहे हैं परेशान, नहीं मिल रहा केसीसी का लोन

माही की गुंज, खवासा। सुनील सोलंकी

एक तरफ प्रदेश सरकार जहां किसानों को हर सुविधा मुहया करवाने का दावा कर रही है। तो वहीं राष्ट्रीयकृत बैंक से लेकर सहकारी संस्था के माध्यम से कई किसानों को जमीन पर केसीसी लोन दिया जाता है। ताकी किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे।

सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज पर साल भर के लिए लोन दिया जाता है। जिसमें किसानों को कृषि (खेती) करने के लिए सहकारी संस्था के माध्यम से लोन वितरण की सुविधा शासन द्वारा कर रखी है। बहु उदेशिय सहकारी संस्था के नियम के अनुसार मार्च से मार्च तक साल भर तक किसानों को बिना ब्याज पर लोन दिया जाता है। साथ ही कई किसानो को जो सहकारी संस्था के सदस्य बने हुए हैं। उन्हें सहकारी संस्था के माध्यम से यूरिया के साथ डीएपी खाद आदि देने का प्रावधान भी शासन ने कर रखा है। लेकिन इस सत्र में न जाने क्या स्थिति निर्मित हुई कि, बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं में नियमों मे उलझांकर कर रख दिया और किसानों को तीन माह से अधिक समय हो गया लेकिन समय पर केसीसी लोन नहीं मिल पाया। कई किसान आज भी केसीसी के लिए सहकारी संस्थाओं के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन वहां सिर्फ उन्हें आश्वासन ही दिया जा रहा है।

सहकारी संस्था जहां किसानों को हो रही है परेशानी

कुछ ऐसा ही मामला बामनिया शाखा के अधीन आने वाली सहकारी संस्था भामल, खवासा, में सामने आया। जहां कई किसानों ने समय पर लोन तो जमा कर दिया लेकिन दूसरी बार उनको लोन लेने में काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। किसान शैतान चावड़ा, रघुनाथ सिंह राठौर, लक्ष्मण सिंह देवड़ा, भीमसिंह जादव, हिदुसिंह देवड़ा आदि किसानों ने बताया कि, हमने मार्च माह में ही बाजार से भी ब्याज पर पैसा लेकर समय पर सहकारी संस्था में पैसा जमा कर दिया लेकिन अभी तक हमें वापस केसीसी का पैसा नहीं मिल पाया। जहां से ब्याज पर पैसा लिया था उनको भी समय पर पैसा देना है। वही हमें कृषि कार्य में काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। जब समय पर हमने पैसा जमा कर रहे है, और ना ही हम डिफाल्टर हैं तो फिर इस तरह से किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है। शासन-प्रशासन से किसानो ने एक ही मांग की है कि, हमें समय पर लोन दिया जाए।

वही मामले में सहकारी संस्था भामल के मैनेजर रामा प्रजापत ने बताया कि, अपने यहां ही प्रॉब्लम नहीं है, कई जगह प्रॉब्लम आ रही है, कई किसानों की जगह कम है, तो लिमिट भी आगे से कम कर दी गई है। इसकी वजह से परेशानी आ रही है। बाकी जो बचे थे 146 लोग उनके भी लिस्ट मेरे पास आ गई है, 10 से 15 लोग और बाकी है। उनको भी जल्द राशि स्वीकृत मिलने के बाद उनको लोन दिया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422